नई दिल्ली
गुरुवार
24 सितंबर 2026
वर्षः 13, अंकः 21
पृष्ठः 08, मूल्य 2 रु0

E-mail
story@sadbhawna.today
sadbhavnatoday@gmail.com
web: www.sadbhawna.today

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

सद्भावना टुडे

आवाज़ अधिकार की

बिहार कैबिनेटः 24 प्रस्तावों पर मुहर, बेगूसराय में...पेज-05

DELHIN/2014/58158

चुनाव आयोग कठपुतली की तरह कर रहा काम,...पेज-08

एक नजर

सुप्रीम कोर्ट से गौतमबुद्ध नगर डीएम मेधा रूपम को राहत

नई दिल्ली,एजेंसी। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर आंशिक रोक लगा दिया है। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मेधा रुपम की सैलरी से पांच लाख रुपये वसूलने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आकृति की एनएसए के तहत की गई कथित गैरकानूनी गिरफ्तारी से जुड़े मामले में मेधा रुपम की सैलरी से 5 लाख रुपये का मुआवजा वसूलने का निर्देश दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गौतमबुद्ध नगर जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम पर सख्त टिप्पणी की थी। उच्च न्यायालय ने हिरासत को मनमाना बताते हुए गौतमबुद्ध नगर की डीएम मेधा रूपम और दूसरे अधिकारियों के वेतन से आकृति को पांच लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था। दरअसल, अप्रैल में नोएडा में मजदूरों के प्रदर्शन के दौरान आकृति चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये प्रदर्शन मजदूरों के अधिकारों और वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर हुआ था। बाद में जिला प्रशासन ने आकृति पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हुए रासुका लगा दिया था। आकृति ने इस कार्रवाई के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि आकृति की तरफ से हिंसा के लिए लोगों को उकसाने के ठोस सबूत नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना और अपनी बात रखना संविधान से मिला अधिकार है। उच्च न्यायालय ने आकृति की हिरासत को रद्द करते हुए उन्हें पांच लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ये रकम डीएम और दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों के वेतन से वसूली जाए।

ईडी ने 54 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का 37 किलो सोना किया जब्त

नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के गुवाहाटी क्षेत्रीय कार्यालय-1 ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत 54 करोड़ रुपये से अधिक अनुमानित मूल्य का 37.064 किलोग्राम सोना अस्थायी रूप से जब्त किया है। जब्त सोने में 29 बड़े आकार की सोने की छड़ें और 50 छोटे आकार के सोने के टुकड़े शामिल हैं। इसके अलावा करीब 13 ग्राम वजन के चांदी जैसे रंग के धातु के टुकड़े भी जब्त किए गए हैं। ईडी के अनुसार, यह कार्रवाई अक्षय परशुराम बानसोडे और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज मामले में की गई है। असम पुलिस ने 30 जून को गुवाहाटी के खारघुली हातिसिल इलाके में अक्षय परशुराम बानसोडे के कब्जे से यह सोना बरामद किया था। फिलहाल सोना गुवाहाटी स्थित कामरूप मेट्रो कोषागार की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा गया है। ईडी ने असम के कामरूप मेट्रो जिले के लतासिल थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

मामला तस्करी किए गए सोने के संगठित अवैध परिवहन और उसे छिपाने तथा आपराधिक साजिश से संबंधित है। जांच में सामने आया कि अक्षय परशुराम बानसोडे कथित तौर पर कई वर्षों से एक अज्ञात व्यक्ति के निर्देश पर देशभर में सोने का परिवहन कर रहा था। ईडी के अनुसार, यह अज्ञात व्यक्ति कूरियरों के एक संगठित गिरोह को नियंत्रित करता था और सोने के परिवहन के लिए एक कूट पहचान प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता था।

संविधान के तहत मिली जिम्मेदारियों को निष्ठा के साथ निभाने के लिए प्रतिबद्धः चुनाव आयोग

चुनाव आयोग के अंदर दो चुनाव आयुक्तों की असहमतियों के बीच उपजे विवाद पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है और कहा

नई दिल्ली,एजेंसी। चुनाव आयोग ने कहा कि वह संविधान के तहत मिली जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। चुनाव आयोग के अंदर दो चुनाव आयुक्तों की असहमतियों के बीच उपजे विवाद पर चुनाव आयोग ने सफाई दी है और कहा है कि आयोग के अंदर सभी फैसले सर्वसम्मति से हो रहे हैं। वैचारिक मतभेद का मतलब टकराव नहीं समझा जाना चाहिए। किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान अलग-अलग राय और टिप्पणियां होना सामान्य बात है। ये अंतिम फैसला लेने से पहले निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं। न केवल तीनों आयुक्तों, बल्कि आयोग का हर अधिकारी चुनावी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आयोग को अपने सुझाव देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। आयोग ने बयान में कहा कि दस महीनों के दौरान की कुछ खास आंतरिक टिप्पणियों/अवलोकनों को उजागर करना, जबकि बड़ी संख्या में मंजूरियों, फैसलों, निर्देशों और पहलों को नजरअंदाज करना, तस्वीर का केवल एक हिस्सा ही दिखाता है। हाल के महीनों में आयोग ने कई फैसले लेने के साथ ही निर्देश जारी किये हैं तथा लगभग 40 नयी पहलें शुरू की हैं और देश भर में मतदाता सूची संशोधन के संचालन सहित कई चुनावी सुधार किये हैं। ये सभी फैसले पिछले एक साल में पूरे आयोग के सर्वसम्मत फैसलों के परिणाम हैं। आयोग के मुताबिक ईसीआईनेट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म सख्त डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत काम करते हैं। इनमें अनधिकृत छेड़छाड़ या डेटा में बदलाव रोकने के लिए आईटी सुरक्षा जांच और ऑडिट नियंत्रण लागू हैं।

आयोग ने कहा कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का काम निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और जिला निर्वाचन अधिकारियों जैसे वैधानिक अधिकारी कानून के तहत अपने निर्धारित अधिकारों के अनुसार करते हैं। यानी आयोग के अनुसार यह अधिकार तय कानूनी प्रक्रिया के तहत इस्तेमाल किये जाते हैं। आयोग के मुताबिक किसी फैसले को अंतिम रूप देने से पहले सदस्यों के बीच चर्चा होती है और इस दौरान अलग-अलग राय, सुझाव या प्रशासनिक सवाल उठना सामान्य प्रक्रिया है। इनका उद्देश्य चुनावी व्यवस्था को मजबूत करना और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करना है।

असहमति के बाद भी सहयोगी आयुक्तों को तरजीह नहीं देते ज्ञानेश कुमार, तत्काल दें इस्तीफा : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'वोट चोरी' की प्रक्रिया में भूमिका निभाने और अपने सहयोगी चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों तथा अधिकारों को तरजीह नहीं देने का आरोप लगाते हुए तत्काल पद से इस्तीफा देने की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बुधवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जिस व्यक्ति के कारण 13 करोड़ से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाये गये हैं उसे संवैधानिक पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उसे तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि दो चुनाव आयुक्तों ने पिछले 10 महीनों में मुख्य चुनाव आयुक्त के कामकाज और विभिन्न फैसलों पर 14 बार लिखित विरोध और असहमति दर्ज करायी है लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है। श्री सिंघवी ने कहा कि 1995 में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्तों से ऊपर नहीं हैं और तीनों समान हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त 'फर्स्ट अमंग इक्वल्स' यानी बराबरों में प्रथम हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय ने चुनाव आयोग को बहुसदस्यीय संस्था बताते हुए कहा था कि सभी चुनाव आयुक्तों की निर्णय प्रक्रिया में भूमिका होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगस्त 2026 में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने फॉर्म-6 में किये गये बदलावों को 'अनधिकृत और अवैध' बताया था जबकि चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने भी इसका विरोध किया था। मई 2026 में दोनों चुनाव आयुक्तों ने इस बात पर आपत्ति जतायी थी कि उनके निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को चुनाव आयोग के पोर्टल तक पहुंच नहीं दी गयी।

प्रधानमंत्री ने 'आयुष्मान भारत' के आठ वर्ष पूरे होने पर की योजना की उपलब्धियों की सराहना

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वास्थ्य सेवा पहल 'आयुष्मान भारत' के आठ वर्ष पूरे होने पर योजना की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि आज 60 करोड़ से अधिक लोगों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी पोस्ट में कहा कि आठ वर्ष पहले आयुष्मान भारत की शुरुआत इस सोच के साथ की गई थी कि देश के हर नागरिक को बेहतर और सस्ती चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें।

उन्होंने कहा कि योजना के तहत करोड़ों नागरिकों को पांच लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत के माध्यम से लोगों के चिकित्सकीय खर्च में बड़ी बचत संभव हुई है। इसका व्यापक लाभ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मिला है। योजना ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए गंभीर बीमारियों के इलाज से जुड़े खर्च के बोझ को कम करने में मदद की है। प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को घर-घर के करीब पहुंचाने की दिशा में हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि देशभर में स्थापित 'आयुष्मान आरोग्य मंदिर' प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन केंद्रों पर अब तक 500 करोड़ से अधिक लोगों की विजिट दर्ज की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के विस्तार से जमीनी स्तर पर प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिली है और लोगों को अपने आसपास स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं। इससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को अधिक व्यापक बनाने में मदद मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत का विस्तार देश में स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में किए गए प्रयासों का हिस्सा है। इस अवसर पर उन्होंने योजना के सभी लाभार्थियों को शुभकामनाएं भी दीं।

दिनकर की जयंती पर मोदी ने दी श्रद्धांजलि, कहा- उनकी रचनाएं युगों तक करेंगी मार्गदर्शन

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि जनचेतना और राष्ट्रीय गौरव की भावनाओं से ओतप्रोत दिनकर की ओजस्वी कविताएं आज भी देशवासियों के हृदय में शौर्य, तेज और आत्मगौरव का संचार करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा कि राष्ट्रकवि दिनकर की रचनाएं साहित्य को समृद्ध करने के साथ-साथ देशवासियों में मातृभूमि के प्रति भक्ति और राष्ट्रभाव की भावना भी जागृत करती हैं।

एसएंडपी ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर सात फीसदी किया

नई दिल्ली,एजेंसी। मूडीज और फिच रेटिंग्स के बाद वित्तीय शोध और साख निर्धारित करने वाली एजेंसी एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने बुधवार को चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर सात फीसदी कर दिया है। एसएंडपी ने बुधवार को 'इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर एशिया पैसिफिक' शीर्षक से जारी अपनी ताजा रिपोर्ट में चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 6.6 फीसदी से बढ़ाकर 7.0 फीसदी कर दिया है। साथ ही एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति औसतन 5.1 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मजबूत औद्योगिक गतिविधियों, स्वस्थ खपत, वस्तुओं के मजबूत निर्यात और सरकारी निवेश में तेजी जैसे कारकों ने आर्थिक वृद्धि को गति दी है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में उम्मीद से बेहतर 7.8 फीसदी रही। एजेंसी ने कहा, ''इसी कारण हमने 31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान पहले के 6.6 फीसदी से बढ़ाकर सात फीसदी किया है।

एसएंडपी ने कहा, ''हमारा अनुमान है कि सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति औसतन 5.1 फीसदी रहेगी। एजेंसी ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) चालू वित्त वर्ष 2026-27 में अपनी नीतिगत दर में 0.25 फीसदी की वृद्धि करेगा।'' उल्लेखनीय है कि इससे पहले फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2026-27 की जीडीपी वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.9 फीसदी कर दिया, जबकि पिछले हफ्ते वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान को बढ़ाकर सात फीसदी कर दिया था। यह जी20 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक वृद्धि दर का अनुमान है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर बीते वित्त वर्ष 2025-26 में 7.8 फीसदी रही थी।

कांची की आध्यात्मिक भूमि से विश्व कल्याण का संदेश, आचार्यों से मिले भागवत

कांचीपुरम/नई दिल्ली। कांची की प्राचीन आध्यात्मिक भूमि से बुधवार को भारतीय संस्कृति की उस वैश्विक चेतना का संदेश निकला, जो अपने लिए ही नहीं, समूची मानवता के कल्याण की कामना करती है। वेदमंत्रों की गूंज, वैदिक अनुष्ठानों और आचार्यों के सानिध्य के बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने वामन जयंती के अवसर पर ओरिक्कै में चातुर्मास्य कर रहे कांची आचार्यों से भेंट की। आयोजन में राष्ट्र और समाज के साथ पूरे विश्व की शांति, समृद्धि और सुख की कामना भारतीय संस्कृति के 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' भाव को सामने ले आई। भागवत ने श्रीकांची कामकोटि पीठम् के जगद्गुरु शंकर विजयेंद्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामिगल द्वारा किए जा रहे श्री चंद्रमौलीश्वर स्वामी के अभिषेक के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने वैदिक विद्वानों द्वारा समाज, राष्ट्र और समस्त विश्व के कल्याण के लिए किए जा रहे वेदपाठ, जप और विशेष प्रार्थनाओं में भाग लिया।

वित्त मंत्रालय 12 अक्टूबर से शुरू करेगा बजट-पूर्व बैठकें, नवंबर तक चलेगा बैठकों का दौर

नई दिल्ली,एजेंसी। वित्त मंत्रालय केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत 12 अक्टूबर से बजट-पूर्व बैठकों की शुरुआत करेगा। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये बैठकें 13 नवंबर तक चलेंगी। वित्त मंत्रालय के बजट विभाग ने बुधवार को जारी एक नोटिस में बताया कि वित्त वर्ष 2027-28 के केंद्रीय बजट से जुड़ी बजट पूर्व बैठकें 12 अक्टूबर से शुरू होकर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 13 नवंबर, 2026 तक चलेंगी। एक माह तक चलने वाली इस बैठक की सूचना सभी मंत्रालयों और विभागों को भी भेजी गई है।

इसमें व्यय विभाग के साथ होने वाली बैठकों का कार्यक्रम दिया गया है। मंत्रालय ने कहा, ''अनुदान और विनियोग के संबंध में चालू वित्त वर्ष 2026-27 के संशोधित अनुमान और 2027-28 के केंद्रीय बजट अनुमान को अंतिम रूप देने के लिए बजट-पूर्व चर्चा 12 अक्टूबर से व्यय सचिव की अध्यक्षता में शुरू होगी। मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम तैयार किया गया है और इसे काफी पहले जारी किया जा रहा है। सूचना के अनुसार मंत्रालयों और विभागों को बैठकों के लिए जरूरी जानकारी छह अक्टूबर, 2026 तक जमा करनी होगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ये बैठकें 13 नवंबर तक चलेंगी। बजट-पूर्व बैठकों के पूरा होने के बाद वित्त वर्ष 2027-28 के बजट अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दिया जाएगा। अगले वित्त वर्ष के बजट में आर्थिक वृद्धि को और तेज करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ रोजगार सृजन और घरेलू मांग को बढ़ावा देने के उपायों पर जोर दिए जाने की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि अगामी वित्त वर्ष 2027-28 का केंद्रीय बजट एक फरवरी को पेश किए जाने की संभावना है। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का चौथा बजट और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार दसवां बजट होगा।

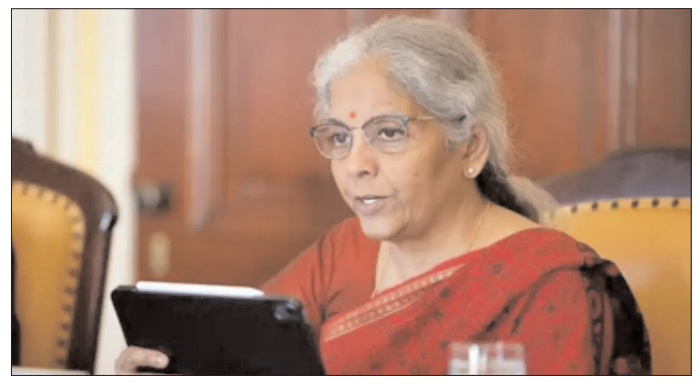

गृह मंत्रालय ने 52 हजार से अधिक जन शिकायतों का निपटारा किया, विशेष अभियान 6 में लंबित मामलों पर जोर

नई दिल्ली,एजेंसी। गृह मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय एवं बाहरी कार्यालयों ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच 52,050 जन शिकायतों और 7,410 शिकायत अपीलों का निपटारा किया, जबकि 761 स्वच्छता अभियान चलाए और 1,02,084 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया। मंत्रालय अब विशेष अभियान 6 के तहत लंबित मामलों के निपटारे और स्वच्छता पर विशेष जोर देगा। मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इस अवधि में सांसदों के 299, राज्य सरकारों के 336 और प्रधानमंत्री कार्यालय के सात संदर्भों का भी निपटारा किया गया। विशेष अभियान 6 का तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर और कार्यान्वयन चरण दो से 31 अक्टूबर तक चलेगा।

अभियान के दौरान जनता से सीधे जुड़े क्षेत्रीय और बाहरी

कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय का लक्ष्य स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल बनाने के साथ लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करना है। अभियान में सांसदों और राज्य सरकारों के संदर्भों, संसद आश्वासनों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, जन शिकायतों और अपीलों के अलावा रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों को अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा गया है। अभियान की प्रगति की निगरानी मंत्रालय के स्तर पर की जा रही है।मंत्रालय के अनुसार, अभियान से संबंधित आंकड़ों को एकत्र और सत्यापित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को संस्थागत रूप देना है।

भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बड़ा फेरबदल

28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नए प्रभारी, 2027 के चुनावों से पहले संगठन को नई दिशा

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को संगठन के स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों के लिए नए प्रदेश प्रभारी और सह-प्रभारियों की नियुक्ति कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की ओर से घोषित इस सूची को महज पदों की अदला-बदली मानना शायद तस्वीर को छोटा करके देखने जैसा होगा। 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच भाजपा ने राज्यों में अपनी संगठनात्मक मशीनरी को नए सिरे से सजाया है। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा ने इस बार सिर्फ प्रभारी बदलकर काम नहीं चलाया। कई बड़े राज्यों में प्रभारी के साथ दो, तीन और चार तक सह-प्रभारी लगाए गए हैं। यानी संगठन का संदेश साफ है। नई व्यवस्था में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश इकाइयों के बीच समन्वय को ज्यादा मजबूत करने की कोशिश दिखाई देती है। खासकर उन राज्यों में जहां

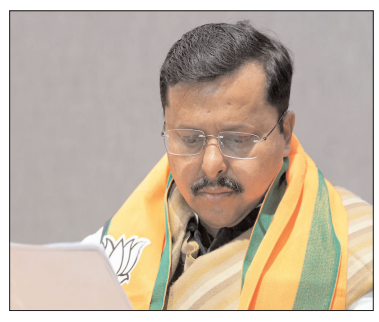

आने वाले समय में चुनावी गतिविधियां तेज होने वाली हैं, वहां जिम्मेदारियों का बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है।

महिलाओं का विशेष ध्यान रखते हुए बीजेपी के कुल 65 प्रभारी और सह प्रभारियों में 21 महिलाओं को भागीदारी देना पार्टी में महिला सशक्तिकरण के रूप में देखा जा सकता है। 4 प्रभारी और 16 सह प्रभारी के साथ भाजपा ने प्रभारियों की सूची में 32% भागीदारी महिलाओं को दी है। सबसे ज्यादा चर्चा उत्तर प्रदेश को लेकर है। देश के सबसे बड़े राजनीतिक राज्य की जिम्मेदारी राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को दी गई है। उनके साथ जगदीश पटेल, मेधा कुलकर्णी, प्रदीप वर्मा और आनंद ओझा को सह-प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में एक प्रभारी के साथ चार सह-प्रभारी लगाए जाने का मतलब संगठन के स्तर पर जिम्मेदारियों का व्यापक बंटवारा है। राज्य का आकार, राजनीतिक महत्व और 2027 के विधानसभा चुनावों की तैयारी इन तीनों को देखते हुए भाजपा यहां संगठनात्मक निगरानी को कई स्तरों पर चलाना चाहती है। महाराष्ट्र में भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा को प्रभारी बनाया गया है। उनके साथ अमित मालवीय, सदानंद शेट तानावडे और कमलजीत सहरावत सह-प्रभारी होंगे। दिल्ली की जिम्मेदारी डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे को मिली है। उनके साथ जमयांग त्सेरिंग नामग्याल और दर्शना जरदोष सह-प्रभारी के तौर पर काम करेंगी। यानी जहां राज्य बड़ा या राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहां भाजपा ने संगठन की 'वन-मैन आर्मी' के बजाय पूरी टीम उतारने का रास्ता चुना है। नई सूची का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। एक नेता, दो राज्यों की जिम्मेदारी। जी हाँ, स्मृति ईरानी को हरियाणा और छत्तीसगढ़, हरीश द्विवेदी को बिहार और कर्नाटक, राम माधव को तमिलनाडु और उत्तराखंड, सतीश पूनिया को पंजाब और जम्मू-कश्मीर तथा सुनील बंसल को तेलंगाना और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दी गई है। यह मॉडल बताता है कि पार्टी कुछ नेताओं के अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का इस्तेमाल एक से ज्यादा राज्यों में करना चाहती है। हालांकि दो राज्यों की जिम्मेदारी सुनने में जितनी प्रभावशाली लगती है, जमीन पर यह उतनी ही मेहनत भी मांगती है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया, बच्चों के साथ बिताया समय

सैफुल्लाह सिद्दीकी, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को सराय काले खां स्थित दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के प्राथमिक सह-शिक्षा विद्यालय में संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का दौरा किया और बच्चों तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत की। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि दिल्ली सरकार बेहतर सुविधाओं, पोषण और देखभाल के साथ आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करने तथा हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अधिक सहयोग और सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, 'हर बच्चे को एक मजबूत शुरुआत मिलनी चाहिए। हर आंगनवाड़ी दीदी के पास इसे संभव बनाने की ताकत होनी चाहिए। यही दिल्ली का सेवा संकल्प है।

मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ बिताए समय का उल्लेख करते हुए कहा कि कोई बच्चा उनके पास आकर बैठ गया, किसी ने उनका हाथ थाम लिया और किसी ने अपनी बात सुनाई। उन्होंने कहा कि बच्चों का यह अपनापन मन में उतर जाता है। उन्होंने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इन बच्चों के सपनों को हर दिन स्नेह से संवारती हैं और कभी शिक्षक तो कभी मां की तरह उनकी देखभाल करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के हर बच्चे की मुस्कान बनी रहे और उसे

संवारने वाली हर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का सम्मान बढ़े, यही सरकार का सेवा संकल्प है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी योजनाओं का संदेश देने वाली 'रैप्ड मेट्रो ट्रेन' को दिखाई हरी झंडी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आईटीओ मेट्रो स्टेशन से सरकारी योजनाओं और जनकल्याणकारी पहलों के संदेश वाली विशेष 'रैप्ड मेट्रो ट्रेन' को हरी झंडी दिखाई।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल के माध्यम से दिल्ली सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और जनहितकारी पहलों की जानकारी अधिक से अधिक नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि पात्र लोग इनका लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ने बताया कि पांच मेट्रो ट्रेनों के 36 कोचों को दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित संदेशों से सजाया गया है। ये ट्रेनें रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन और वॉयलेट लाइनों पर संचालित होंगी और दिल्ली मेट्रो नेटवर्क के लगभग 67 प्रतिशत हिस्से को कवर करेंगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य सरकार की योजनाओं की जानकारी पात्र नागरिकों तक सरल और प्रभावी तरीके से पहुंचाना है, ताकि अधिक से अधिक दिल्लीवासी इन जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।

दिल्ली के परिवहन मंत्री से बैठक के बाद जिला अदालतों के वकीलों ने हड़ताल का फैसला वापस लिया

शाहनवाज सैफ, सद्भावना टुडे

नई दिल्ली। दिल्ली की निचली अदालतों के वकील मोटर व्हीकल रुल्स के रुल 167 में संशोधन के खिलाफ 24 सितंबर को दिल्ली के वकीलों की होने वाली हड़ताल और उप-राज्यपाल के घेराव का कार्यक्रम वापस ले लिया गया है। कोआर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बार एसोसिएशंस ऑफ दिल्ली के प्रतिनिधियों और दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह के साथ हुई बैठक के बाद आंदोलन के इस कार्यक्रम को वापस ले लिया गया है।

कोआर्डिनेशन कमेटी के मुताबिक मोटर व्हीकल रुल्स के संशोधन पर अमल फिलहाल रोक दिया गया है।दिल्ली सरकार के आश्वासन के बाद कोआर्डिनेशन कमेटी ने 24 सितंबर के आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया है। कोआर्डिनेशन कमेटी ने सभी वकीलों से 24 सितंबर को न्यायिक कार्यों में हिस्सा लेने को कहा है। बतादें कि दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी मोटर व्हीकल रुल्स के रुल 167 में संशोधन पर चिंता जताते हुए कहा है कि ये आम नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील एन हरिहरन और सचिव विक्रम सिंह पंवार के हस्ताक्षर से जारी नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की ओर से किया गया संशोधन न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में दखलंदाजी है। इसके पहले, 22 सितंबर को दिल्ली की निचली अदालतों में वकीलों ने हड़ताल का आयोजन किया था। दरअसल दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालानों की सुनवाई के लिए एसडीएम, एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसके पहले ट्रैफिक चालान अदालतों में मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होते थे।

नये संशोधन के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ चालान जारी किया गया है तो या तो उसे चालान भरना होगा या चालान जारी होने के 45 दिनों के अंदर दिल्ली सरकार की ओर से नियत अफसरों के समक्ष इसका विरोध करना होगा। इस संशोधन के तहत अगर किसी व्यक्ति ने 45 दिन के अंदर चालान का विरोध नहीं किया तो ये माना जाएगा कि उसने चालान स्वीकार कर लिया है। अगर दिल्ली सरकार के बताए हुए अधिकारी ने चालान के विरोध में दलील को खारिज कर दिया तो संबंधित व्यक्ति कोर्ट में तभी जा सकता है जब वो चालान की राशि का आधा हिस्सा दिल्ली सरकार के पास जमा करे। दिल्ली सरकार के इस फैसले का कोआर्डिनेशन कमेटी ने विरोध जताते हुए संबंधित मंत्री के समक्ष 27 अगस्त को अपनी बातें रखी थी।

दिल्ली भाजपा के स्वच्छता अभियान एवं पौधरोपण कार्यक्रम में बी.एल. संतोष समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने किया श्रमदान

नई दिल्ली। दिल्ली भाजपा ने बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित लोक निर्माण विभाग के पार्क में स्वच्छता अभियान चलाया और पौधरोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी.एल. संतोष के नेतृत्व में आयोजित स्वच्छता अभियान में दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा, वरिष्ठ राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए।

इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि फ्लाईओवर के नीचे स्थित इस पार्क का क्षेत्र थोड़ा अलग दिखता है जिसके कारण से लोग इसमे कूड़ा मलवा फेंक देते हैं। आज के स्वच्छता अभियान में सम्मिलित सभी राष्ट्रीय एवं प्रदेश पदाधिकारियों ने मिल कर नगर निगम कर्मियों के द्वारा लाये वाहनों के माध्यम से लोक निर्माण विभाग के विशाल पार्क के चारों तरफ एकत्र लगभग 5 टेम्पो मलवा एवं कूड़ा उठाया और तत्पश्चात पार्क में सभी ने एक-एक पौधा लगाया। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता, सांसद, विधायक एवं पार्षद 25 सितंबर से 2 अक्टूबर 2026 के बीच सारी दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलायेंगे जिनमें विशेषकर पार्कों, पूजा स्थलों, अस्पताल परिसरों पर ध्यान दिया जायेगा।

दिल्ली नगर ने प्रवर्तन अभियान के तहत 35 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा खतरनाक भवनों, अनधिकृत निर्माण तथा दिल्ली के मास्टर प्लान (एमपीडी) और भवन उपनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध राजधानी में जारी व्यापक प्रवर्तन अभियान के तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। भवन निर्माण संबंधी मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा जनसुरक्षा के दृष्टिगत निगम के सभी 12 जोनों में सख्त प्रवर्तन कार्रवाई की जा रही है।

आज की गहन प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान सभी 12 जोनों में 35 ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गईं, जबकि 5 संपत्तियों को सील किया गया तथा भवन निर्माण संबंधी मानदंडों के उल्लंघन के मामलों में 4 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए। निगम द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में लगातार निगरानी रखते हुए चिन्हित उल्लंघनों के विरुद्ध निर्धारित नियमों एवं प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई। एमसीडी द्वारा कल भी व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया गया था, जिसके दौरान एमपीडी एवं भवन उपनियमों के उल्लंघन के मामलों में 42 संपत्तियों

के विरुद्ध ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई तथा 7 संपत्तियों को सील किया गया।

दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई

आज के प्रवर्तन अभियान के दौरान दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख ध्वस्तीकरण कार्रवाई की गई। इनमें खड्डा कॉलोनी, पुल पहलादपुर, नंगली सकरावती, पालम, राशिद मार्केट, शकरपुर, पश्चिम विनोद नगर, शिव विहार, करावल नगर तथा गणेश नगर एक्सटेंशन सहित अन्य स्थान शामिल हैं। एमसीडी ने दोहराया कि निगम क्षेत्राधिकार में अनधिकृत निर्माण तथा भवन निर्माण संबंधी मानदंडों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। फील्ड अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखें तथा एमपीडी, भवन उपनियमों एवं अन्य संबंधित नियमों के लागू प्रावधानों के तहत उल्लंघनों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। सभी 12 जोनों में यह प्रवर्तन अभियान आगे भी जारी रहेगा। अनधिकृत निर्माण, खतरनाक भवनों तथा जनसुरक्षा के लिए जोखिम उत्पन्न करने वाले अन्य उल्लंघनों के विरुद्ध निगम द्वारा निरंतर निगरानी एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

झूसू चुनाव के बाद विजय जुलूस पर रोक के आदेश का पालन नहीं करने पर डीयू को हाई कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के चुनाव परिणाम के बाद विजय जुलूस नहीं निकालने के उसके आदेश का पालन नहीं करने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी (डीयू) को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूछा है कि उनके खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही क्यों नहीं शुरु की जाए। हालांकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस साल के चुनाव में सार्वजनिक संपत्तियों का विरुपण देखने को नहीं मिला, ये एक बड़ी उपलब्धि है। उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव के उम्मीदवारों से पूछा कि आपसे लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों पर अमल नहीं करने पर चुनावी नुकसान की भरपाई क्यों नहीं की जाए। वकील प्रशांत मनचंदा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में नयी अर्जी दाखिल कर कहा है कि उच्च न्यायालय के 17 सितंबर के आदेश का उल्लंघन करते हुए 19 सितंबर को दिल्ली यूनिवर्सिटी ओर दूसरी जगहों पर जीते हुए उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने डूसू चुनाव परिणाम आने के बाद दिल्ली में जीत का कोई भी जुलूस निकालने पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि हम डूसू चुनाव में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर चुनाव संतोषजनक तरीके से संपन्न नहीं कराए गए, तो हम पदाधिकारियों का काम रोक सकते हैं। कोर्ट ने 15 सितंबर को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को चेतावनी दी थी कि अगर नियमों और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया, तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि डूसू के चुनाव में छात्र संगठनों की बड़ी भूमिका है। कोर्ट ने छात्र संगठनों के पदाधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे अपने उम्मीदवारों को निर्देश दें कि वो नियमों का पालन करें।

निगमायुक्त संजीव खिरवार ने बालक राम अस्पताल और वजीराबाद का किया निरीक्षण

सद्भावना टुडे, वरिष्ठ संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने बुधवार को उत्तरी क्षेत्र स्थित बालक राम अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया और अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नागरिकों की सुविधा के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान तिमारपुर के विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, अतिरिक्त आयुक्त पंकज नरेश अग्रवाल, उत्तरी क्षेत्र की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी, प्रमुख अभियंता के.के. शर्मा सहित दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। निगमायुक्त श्री खिरवार ने अस्पताल में नागरिकों के सुचारू आवागमन को ध्यान में रखते हुए मुख्य एप्रोच सड़क से अस्पताल के प्रवेश द्वार तक मार्ग को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर में स्थित पेड़ के पुनर्स्थापन के भी आदेश दिए, ताकि अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा चिकित्सीय सेवाओं का सुचारू संचालन सुनिश्चित किया जा सके।

उन्होंने अस्पताल में आवश्यकतानुसार

पर्याप्त संख्या में कार्यबल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए, जिससे अस्पताल की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाया जा सके और मरीजों को समय पर सुविधाएं मिल सकें।

इसके बाद निगमायुक्त ने उत्तरी क्षेत्र के वजीराबाद इलाके का निरीक्षण किया और स्थानीय नागरिकों की समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र की नालियों से गाद निकालकर उनकी समुचित सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। श्री खिरवार ने कहा कि नालियों की सफाई में बाधक बने रैंपों को हटाकर नालियों की उचित ढंग से सफाई की जाए, ताकि जल निकासी व्यवस्था बेहतर हो और स्थानीय नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश भी दिए।

दिल्ली के उपराज्यपाल ने सभी पार्कों की सुरक्षा के दिए निर्देश

नई दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिल्ली के सभी पार्कों का सुरक्षा करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बुधवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार , दिल्ली नगर निगम आयुक्त संजीव खिरवार और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एन सरवना कुमार के साथ बैठक की। उपराज्यपाल ने बैठक के दौरान दिल्ली के सभी पार्कों का एक हफ्ते के अंदर व्यापक सुरक्षा ऑडिट करने का निर्देश दिया।

इसमें पर्याप्त लाइटिंग, सुरक्षा, नियमित पेट्रोलिंग और साफ-सफाई पर खास जोर दिया गया। उन्होंने दिल्ली पुलिस को बीट पेट्रोलिंग को मजबूत करने और पार्क के आस-पास पिंक पुलिस कर्मियों की तैनाती का निर्देश दिया। उपराज्यपाल ने दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण को पार्कों की लगातार देखभाल के लिए आरड्ब्लूए, निजी संस्थाओं और स्थानीय शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर काम करने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा। उन्होंने कह कि दिल्ली के नागरिकों के बेहतर जीवन स्तर के लिए सुरक्षित, साफ और आसानी से पहुंच वाले पार्क जरूरी हैं। इसके अलावा उपराज्यपाल ने आज यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिंग सेंटर (यूटीटीआईपीईसी) की 70वीं गवर्निंग बॉडी बैठक की अध्यक्षता की। इसमें दिल्ली के कॉरिडोर में भीड़ कम करने और शहरी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए बड़े रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी-मॉडल इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की गई। उपराज्यपाल ने पूरी राजधानी में आसान परिवहन एकीकरण, पैदल चलने वालों के लिए कनेक्टिविटी और 'लास्ट-माइल एक्सेस' (गंतव्य तक आखिरी चरण की पहुंच) पर केंद्रित अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी।

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने जीबी पंत अस्पताल का किया निरीक्षण, दवाओं की उपलब्धता एवं सुविधाओं की समीक्षा की

नई दिल्ली। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने बुधवार को जीबी पंत अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और अस्पताल के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। दवाओं के स्टोर और फ़ार्मेसी के निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह को अस्पताल प्रशासन ने बताया कि लगभग 95-97 फीसदी दवाएं उपलब्ध हैं। इस पर मंत्री ने अस्पताल प्रशासन को तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने और जरूरी दवाओं की 100 प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रोजाना बड़ी संख्या में मरीज़ इलाज के लिए अस्पताल में आते हैं और उन्हें संस्थान द्वारा दी जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं पर पूरा भरोसा है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जरूरी दवाओं की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित करके इस भरोसे को और अधिक मजबूत किया जाना चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री ने दवाओं की उपलब्धता का खुद जायजा लेने के लिए फार्मेसी और दवा भंडारण क्षेत्रों में रैंडम स्पॉट चेक किए। निरीक्षण के दौरान उन्हें बताया गया कि अगर किसी खास ब्रांड का स्टॉक उपलब्ध नहीं है, तो उसकी दूसरी कंपनियों की वैकल्पिक ब्रांड की दवाएं उपलब्ध हैं। मंत्री ने डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को ऐसे मामलों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर द्वारा लिखी गई कोई खास ब्रांड की दवा उपलब्ध नहीं है, तो मरीजों को उसी सॉल्ट/जेनेरिक कंपोजीशन वाले उपलब्ध विकल्प के बारे में विस्तार से जानकारी दी जानी चाहिए, बशर्ते यह चिकित्सकीय रूप से उचित हो। अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मंत्री ने अलग-अलग वार्डों का भी दौरा किया और इलाज, दवाओं की उपलब्धता और अस्पताल की अन्य सुविधाओं के बारे में मरीजों और उनके साथ आए लोगों से खुद बातचीत कर फीडबैक लिया। उन्होंने इस बारे में भी जानकारी हासिल की कि क्या मरीजों को दवाएं समय पर मिल रही है या नहीं और क्या मरीजों को मेडिकल की सेवाएं पाने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल के कर्मचारियों से खुद बातचीत कर मरीज़ों के लिए की जा रही सभी व्यवस्थाओं का बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दवाओं के स्टॉक के बारे में सतर्क रहने और स्टॉक खत्म होने से पहले समय पर दवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

दिल्ली में 'दुर्गा' योजना को मंजूरी, 1,300 गुलाबी ई-ऑटो मिलेंगे

नई दिल्ली,एजेंसी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार देने के लिए 'दुर्गा' योजना स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वूमेन/ट्रांसजेंडर ग्रीन ई-ऑटो यानी 'दुर्गा' योजना को स्वीकृति दे दी गई। योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी इलेक्ट्रिक ऑटो दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को इलेक्ट्रिक ऑटो का मालिक और चालक बनने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिलाओं और ट्रांसजेंडर्स को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के साथ उन्हें सुरक्षित परिवहन से जोड़ना दिल्ली सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। 'दुर्गा' योजना इसी दिशा में अहम पहल है। इसके अंतर्गत महिलाएं और ट्रांसजेंडर इलेक्ट्रिक ऑटो के मालिक और चालक बन सकेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'दुर्गा' योजना के पहले चरण में 1,300 गुलाबी रंग के इलेक्ट्रिक ऑटो पंजीकृत करने का प्रस्ताव है। इनमें 1,170 इलेक्ट्रिक ऑटो महिलाओं के लिए और 130 इलेक्ट्रिक ऑटो ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए होंगे। महिलाओं के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में

अधिकतम 90 इलेक्ट्रिक ऑटो और ट्रांसजेंडर लाभार्थियों के लिए प्रत्येक राजस्व जिले में अधिकतम 10 इलेक्ट्रिक ऑटो तक की सीमा रखी गई है। आवेदक योजना के लिए बनाए गए समर्पित ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। योजना का लाभ निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों को मिलेगा। दुर्गा योजना में महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष की आयु, दिल्ली का निवासी होना, वैध मतदाता पहचान पत्र, एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस और पीएसवी बैज जैसी शर्तें रखी गई हैं। तीन से अधिक बच्चों वाली महिला इस योजना की पात्र नहीं मानी जाएगी। महिला आवेदक या उसके परिवार के पास कोई पंजीकृत परिवहन वाहन या श्री-व्हीलर नहीं होना चाहिए तथा वित्त वर्ष 2025-26 में परिवार की आय पांच लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ट्रांसजेंडर आवेदकों के लिए दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय से जारी वैध ट्रांसजेंडर प्रमाण-पत्र, 20 से 40 वर्ष की आयु, दिल्ली का निवासी होना, वैध मतदाता पहचान पत्र, एलएमवी लाइसेंस और पीएसवी बैज अनिवार्य होंगे। दुर्गा योजना के तहत ई-ऑटो पर तीन वर्ष की अनिवार्य लॉक-इन अवधि होगी। इस अवधि में वाहन को बेचा, हस्तांतरित या अन्य तरीके से निस्तारित नहीं किया जा सकेगा। योजना को सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ने के लिए भी विशेष व्यवस्था प्रस्तावित है। डीएमआरसी ने बताया है कि 70 मेट्रो स्टेशनों की पार्किंग में पहले से ही ईवी चार्जिंग सुविधाओं के लिए स्थान उपलब्ध कराया जा चुका है। यह योजना केवल रोजगार उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े सहायक क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। करीब 1,300 ई-ऑटो के संचालन से मरम्मत कार्यशालाओं, सर्विसिंग, चार्जिंग और बैटरी रीसाइक्लिंग जैसी सेवाओं में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। योजना के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव का समय-समय पर आकलन भी किया जाएगा।

एक नजर

विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, एक गिरफ्तार

गुरुग्राम। विदेश में वर्क वीजा पर नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से 12 लाख रुपये ठग लिए गए। ठगी के गिरोह के मुख्य आरोपी को गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि आरोपी ने रजिस्टर्ड फर्म का झांसा देकर यह ठगी की। जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 2025 को थाना शहर गुरुग्राम में एक युवक ने शिकायत दी थी कि टिंकू नाम के व्यक्ति ने बताया कि उसकी गुरुग्राम में एल.के. इन्टरप्राइजिज नाम से सरकार द्वारा रजिस्टर्ड फर्म है। उसने शिकायतकर्ता और उसके साथी को रूस में वर्क वीजा पर नौकरी दिलाने के नाम पर 12 लाख रुपये खर्चा बताया। पीड़ितों ने विश्वास करके बैंक खातों और नकद के माध्यम से लाखों रुपये दे दिए। आरोपी ने वर्क वीजा के बजाय उन्हें टूरिस्ट वीजा पर रूस भेज दिया, जहां एयरपोर्ट से ही उन्हें डिपोर्ट कर वापस भेज दिया गया। जब पीड़ितों ने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने उन्हें टरकाने के लिए वर्क वीजा पर थाईलैंड और मलेशिया भेज दिया। आरोप है कि मलेशिया में आरोपी के अन्य एजेंटों ने उनके पासपोर्ट छीन लिए, बंधक बनाया और मारपीट की। किसी तरह पैसे मंगवाकर वे भारत लौटे और जब दोबारा पैसे मांगे तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी। शिकायत पर थाना शहर में संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया। थाना शहर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को 22 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान टिंकू बैसवाल (33 वर्ष) निवासी गांव भैंसवाल जिला सोनीपत के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी अपनी फर्म के नाम पर विदेश भेजने का झांसा देकर भारी रकम ऐंठता था। वर्क वीजा के नाम पर पैसे लेकर टूरिस्ट वीजा देता था और फिर अपने विदेशी/स्थानीय एजेंटों के साथ मिलकर युवकों को दूसरे देशों में घुमाता था। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य विदेशी और स्थानीय एजेंटों, वित्तीय लेन-देन और फर्जी दस्तावेजों की जांच कर रही है।

मंदिर से चांदी के तीन छत्र चोरी, आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम। फर्रुखनगर क्षेत्र के गांव झांझरोला खेड़ा स्थित श्याम बाबा मंदिर में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए तीन चांदी के छत्र बरामद किए हैं। आरोपी की पहचान गांव कालियावास निवासी अमित कुमार (42) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, 20/21 सितंबर की रात को एक व्यक्ति ने श्याम बाबा मंदिर से चांदी के छत्र चोरी कर लिए थे। इस संबंध में 21 सितंबर को शिकायत मिलने पर थाना फर्रुखनगर में मामला दर्ज किया गया था। मामले की जांच करते हुए फर्रुखनगर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की और 22 सितंबर को झांझरोला खेड़ा मोड़ से आरोपी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी पहले एक कंपनी में काम करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद वह परेशान रहने लगा था। इसी परेशानी के दौरान उसने मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किए गए तीनों चांदी के छत्र बरामद कर लिए हैं। मामले में पुलिस की ओर से नियमानुसार आगामी कार्रवाई की जा रही है और जांच जारी है।

बाइकर्स लुटेरो ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में पांच लोगों के साथ की लूटपाट

नोएडा। नोएडा में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बाइक सवार बदमाशों ने पांच लोगों को निशाना बनाकर लूटपाट की। बदमाश चार लोगों के मोबाइल फोन, जबकि एक महिला के गले से सोने की चेन और लॉकेट लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने सभी मामलों में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-39 थाना के प्रभारी डीपी शुक्ला ने बुधवार को बताया कि काशीराम कॉलोनी सेक्टर-45 निवासी भानु प्रताप सिंह ने आज सुबह तहरीर दी है कि मंगलवार की शाम को वह घूमने निकले थे। तभी सेक्टर-44 के पास अज्ञात बदमाश उनका आईफोन छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में सफल रहे। सेक्टर-49 थाना के प्रभारी राम प्रकाश शर्मा ने बताया कि सेक्टर-76 स्थित सेठी मैक्स रॉल सोसायटी निवासी निकिता पठानिया सुबह ऑटो से कंपनी जा रही थीं। थाना क्षेत्र में पहुंचते ही अज्ञात बदमाशों ने उनका आईफोन छीन लिया। पीड़िता के अनुसार फोन में महत्वपूर्ण निजी और बैंकिंग संबंधी जानकारी थी। इसी तरह फेस-3 थाना के प्रभारी सुभाष चंद्र ने बताया कि गौर सिटी-02 निवासी अभिषेक सिंह बीती रात सेक्टर-62 जा रहे थे। बसई गांव के पास दो बदमाशों ने उनका आईफोन छीन लिया। इसी थाना क्षेत्र की दूसरी घटना में गढ़ी चौखंडी निवासी ईताश से परथला गोलचक्कर के पास बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश मोबाइल लूटकर फरार हो गए। दोनों मामलों में पुलिस जांच कर रही है। बिसरख थाना प्रभारी रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि दीपिका अरोड़ा बीती रात अपने बेटे के साथ महागुन माईवुड सोसायटी के पास से गुजर रही थीं। इसी दौरान बाइक सवार दो बदमाशों ने उनके गले से सोने की चेन और लॉकेट लूट लिया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर बदमाशों की पहचान और तलाश में जुटी है। उक्त सभी मामलों में पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच की कार्रवाई शुरू कर दी है।

फेडरल बैंक ने नकली सोना लेकर जारी किया 1.46 करोड़ का लोन

गाजियाबाद,एजेंसी। फेडरल बैंक की आरडीसी शाखा में सोने के नकली आभूषण गिरवी रखकर 1.46 करोड़ रुपये का गोल्ड लोन लेने के मामले में सिर्फ सोने के आभूषण ही नकली नहीं है बल्कि लोन लेने वाले ग्राहक भी फर्जी हैं। यानि उन्हें गोल्ड लोन की जरूरत नहीं थी और न ही उनके पास लोन के लिए सोना मौजूद था। लोन खातों में दर्ज पतों की पड़ताल में कई नामजद ग्राहक मौके पर मिले ही नहीं। कुछ पते ऐसे भी मिले, जहां संबंधित व्यक्ति के रहने की पुष्टि नहीं हो सकी। आरोपितों ने ऐसे लोगों को ग्राहक बनाकर उनके नाम पर गोल्ड लोन कराया और बैंक में नकली सोने के आभूषण गिरवी रखवाया।

दिल्ली गेट निवासी मयूर बंसल के नाम पर दो गोल्ड लोन में कुल 15.94 लाख रुपये जारी हुए। मयूर ने बताया कि उसे एक अन्य आरोपित मोसीम ने लोन दिलाया था। इसके बदले केवल 15 हजार रुपये दिए गए। उसके मुताबिक खाते में आई लोन की रकम मोसीम एवं एक अन्य ने अपने खाते

में ट्रांसफर कराई थी और कुछ रकम नकद ले ली। उसे रुपयों की जरूरत थी इसलिए वह आरोपितों के बहकावे में आ गया। रूपीक कंपनी की ओर से कराई गई मौके की जांच में भी कई पते संदिग्ध मिले। शांतिनगर निवासी कविता और शिवपुरी निवासी मोसिम खान अपने बताए पते पर नहीं मिले। साहिल सिंह और मोसिम खान का पता एक ही दर्ज है। विजयनगर सेक्टर-9 निवासी मुकुल कुमार और प्रताप विहार निवासी अलीबिन हुसैन का पता भी पड़ताल में ट्रेस नहीं हो सका। प्रताप विहार निवासी वसीम अब्बास के घर उसका भाई निसार मिला। उसने बताया कि वसीम काम पर गया है। बाद में वसीम ने फोन पर बताया कि उसने अपने घर का सोना गिरवी रखा था और लोन की किस्त चुका रहा है। रूपीक की जांच में वसीम को पूर्व आरएम अजहर का रिश्तेदार बताया गया है। अलीबिन हुसैन जांच में अजहर के गांव का व्यक्ति होने की बात सामने आई। जांच में सामने आया कि अलीबिन हुसैन को छोड़कर किसी ने लोन की किस्त नहीं चुकाई। तीन किस्त नहीं आने पर खाते एनपीए घोषित किए जाते हैं और रूपीक कंपनी में सभी खाते एनपीए हो चुके हैं।

लिव-इन पार्टनर की पीट-पीटकर हत्या, आरोपी बस चालक गिरफ्तार

गुरुग्राम। पालम विहार इलाके में लिव-इन पार्टनर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या करने के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बुधवार को बताया कि दोनों वर्ष 2020 से लिव-इन में रह रहे थे।

आपसी कहासुनी में हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जानकारी के अनुसार 22 सितंबर 2026 को थाना पालम विहार पुलिस को सूचना मिली कि धर्म कॉलोनी में एक किराए के मकान में महिला खून से लथपथ पड़ी है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मौके पर सीन-ऑफ-क्राइम और फिंगरप्रिंट टीम को बुलाकर साक्ष्य जुटाए। मकान मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। मकान मालिक ने बताया कि गली में शोर सुनकर वह बाहर आया तो देखा कि उसका किराएदार आकाश अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा है। उसने महिला के सिर पर वार किया और मौके से फरार हो गया। शिकायत के आधार पर थाना पालम विहार में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी आकाश (33 वर्ष), निवासी बरेली उत्तर प्रदेश को घटना के 24 घंटे के भीतर ही धर्म कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी गुरुग्राम में बस चालक है और मृतका उसकी पत्नी नहीं, बल्कि लिव-इन पार्टनर थी। दोनों साल 2020 से लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहे थे।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में डीएचबीवीएन ने 51 प्रतिशत लक्ष्य किया हासिल

गुरुग्राम। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) की ओर से रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के काम को तेजी से आगे बढ़ाने का दावा किया गया है। अब तक कुल 51 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। रेवाड़ी और सिरसा सर्कल ने मार्च 2027 तक निर्धारित लक्ष्य को छह महीने पहले वर्ष 2026 में ही पार करते हुए 106-106 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए फतेहाबाद ने 86 प्रतिशत, हिसार ने 63 प्रतिशत, गुरुग्राम-1 ने 41 प्रतिशत, गुरुग्राम-2 ने 48 प्रतिशत, नारनौल ने 46 प्रतिशत, भिवानी ने 45 प्रतिशत तथा जींद ने 37 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है। फरीदाबाद ने 15 प्रतिशत और पलवल ने 11 प्रतिशत उपलब्धि दर्ज की है। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार डीएचबीवीएन द्वारा योजना के तहत शेष पात्र उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया को ओर तेज किया जा रहा है, ताकि मार्च 2027 तक निर्धारित 1,22,000 सौर कनेक्शनों के लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके। कहा गया है कि डीएचबीवीएन में अब तक योजना के तहत 1,01,845 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 62,455 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन संयंत्रों की कुल स्थापित क्षमता 221.90 मेगावाट है। जोनवार प्रगति की बात करें तो इसमें हिसार जोन अग्रणी है। वहां अब तक 62,282 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 36,291 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनकी कुल क्षमता 119.41 मेगावाट है। जोन में 35,952 कनेक्शन जारी किए गए हैं तथा 31,616 लाभार्थियों को 231.36 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। हिसार जोन ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 66 प्रतिशत हासिल कर लिया है। दिल्ली जोन में 39,563 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 26,164 रूफटॉप सोलर संयंत्र, कुल 102.49 मेगावाट क्षमता, स्थापित किए जा चुके हैं। जोन में 25,861 कनेक्शन जारी किए गए हैं तथा 21,016 लाभार्थियों को 149.52 करोड़ रुपये की सब्सिडी वितरित की गई है। दिल्ली जोन ने अपने निर्धारित लक्ष्य का 38 प्रतिशत हासिल किया है। डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने अधिकारियों को लंबित आवेदनों की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करते हुए उनके शीघ्र निपटान तथा निरीक्षण एवं कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, ताकि पात्र उपभोक्ताओं को योजना का लाभ निर्धारित समय में मिल सके।

गाजियाबाद में ट्रेनों ने बढ़ाई यात्रियों की टेंशन, 3 घंटे की देरी से पहुंची दिल्ली-बरेली ईएमयू

अशोक कुमार, सद्भावना टुडे

गाजियाबाद। यात्रियों को रेलवे की अव्यवस्था का खामियाजा भुगतना पड़ा। दिल्ली की ओर आने वाली कई ट्रेनें निर्धारित समय से काफी देर से पहुंचीं। 10 से अधिक ट्रेनों के विलंबित होने से खुर्जा, अलीगढ़, हाथरस, हापुड़, मोदीनगर, मुरादनगर और दादरी समेत आसपास के क्षेत्रों से रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

सबसे ज्यादा असर उन यात्रियों पर पड़ा, जिन्हें सुबह समय से कार्यालय या कालेज पहुंचना था। दिल्ली-बरेली ईएमयू करीब तीन घंटे की देरी से पहुंची। वहीं सूबेदारगंज-आनंद विहार ट्रेन लगभग एक घंटे 51 मिनट और उत्कल एक्सप्रेस एक घंटे 55 मिनट लेट रही। दिल्ली-जगाधरी एक्सप्रेस भी करीब एक घंटे 17 मिनट की देरी से चली। दनकौर-दिल्ली ईएमयू लगभग 31 मिनट देर से पहुंची। जबकि बरेली-भुज एक्सप्रेस करीब 27 मिनट देरी से चली। इनके अलावा अलीगढ़-दिल्ली ईएमयू, हाथरस-दिल्ली ईएमयू और बुलंदशहर-गाजियाबाद ईएमयू के संचालन पर भी देरी का असर रहा। सुबह के समय ट्रेनों में देरी होने का सीधा असर

यात्रियों की दिनचर्या पर पड़ा। रोजाना ट्रेन से दिल्ली और आसपास के इलाकों में नौकरी के लिए आने वाले कई यात्री समय से अपने कार्यालय नहीं पहुंच सके। कुछ यात्रियों को कार्यालय पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ा। कालेज जाने वाले छात्रों की परेशानी भी कम नहीं रही। ट्रेन देर से आने के कारण कई छात्र निर्धारित समय पर कक्षाओं में नहीं पहुंच पाए। रोजाना ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का कहना है कि ट्रेन के समय में लगातार होने वाली अनिश्चितता से उनके कामकाज और पढ़ाई का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है।

गुरुग्रामः सेवा सेतु कैंप में 300 से अधिक लोगों ने ली सरकारी योजनाओं की जानकारी

गुरुग्राम,एजेंसी। सेवा संकल्प अभियान के तहत बुधवार को नगर निगम मानेसर के गांव नखड़ौला स्थित खेल स्टेडियम में सेवा सेतु कैंप लगाया गया। इसका उद्देश्य आमजन को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उनके घर-द्वार के नजदीक उपलब्ध कराने तथा पात्र नागरिकों को योजनाओं से सीधे जोडऩा रहा। कैंप का शुभारंभ नगर निगम मानेसर के सीनियर डिप्टी मेयर प्रवीण यादव तथा वार्ड नंबर-15 की पार्षद पिंकी ने किया।

सेवा सेतु अभियान के तहत मानेसर में आयोजित यह पहला कैंप था। इसके बाद 24 सितंबर को नगर निगम मानेसर के सेक्टर-8 स्थित मुख्यालय में भी कैंप आयोजित किया जाएगा। इन सेवा सेतु कैंपों में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर नागरिकों को सरकार की योजनाओं, सेवाओं एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी देने के साथ पात्र लाभार्थियों को मौके पर ही संबंधित योजनाओं से जोडऩे की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। कैंप में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर 300 से अधिक लोगों को सरकार की योजनाओं एवं विभागीय सेवाओं के बारे में जागरूक किया

गया। विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नागरिकों को पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी। वहीं पात्र लाभार्थियों का मौके पर ही पंजीकरण किया गया, जिससे लोगों को संबंधित कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता न पड़े। कैंप में पहुंचे नागरिकों ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर जाकर अपनी जरूरत के अनुसार योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त की तथा अधिकारियों से अपनी समस्याओं और पात्रता से संबंधित जानकारी भी ली। सेवा सेतु कैंप में 62 महिलाओं ने दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए ऑन द स्पॉट अपना पंजीकरण कराया। गांव पंचगांव निवासी अनु तथा पूजा ने बताया कि सेवा सेतु कैंप में उन्हें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जानकारी मिली और मौके पर ही उनका पंजीकरण कर दिया गया। शिकोहपुर निवासी सुनीता ने कहा कि सेवा सेतु कैंप में उन्हें दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की जानकारी मिली और ऑन द स्पॉट पंजीकरण की सुविधा का लाभ मिला।

समय पूरा कर चुके 552 वाहनों को पुलिस ने किया इंपाउंड

गुरुग्राम। ट्रैफिक पुलिस ने समय सीमा पूरी कर चुके वाहनों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया। अभियान के तहत एक से 22 सितंबर तक विभिन्न स्थानों पर जांच के दौरान 552 वाहनों को इंपाउंड किया गया। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, अभियान के दौरान बीएस-3 एवं उससे नीचे के वाहनों के साथ-साथ निर्धारित अवधि पूरी कर चुके वाहनों की जांच की जा रही है। नियमों के तहत डीजल वाहनों के 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के 15 वर्ष पूरे होने के बाद सडक़ पर संचालन प्रतिबंधित है। पुलिस की ओर से वाहन चालकों को इस संबंध में लगातार जागरूक भी किया जा रहा है। इसके लिए सुरक्षा रथ के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने वाहनों के दस्तावेज और उनकी वैधता की जांच की। निर्धारित मानकों का उल्लंघन मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहनों को इंपाउंड किया गया। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे सरकार द्वारा निर्धारित मानकों और यातायात नियमों का पालन करें।

गुरुग्रामः मेडिकल कालेजों में चार साल से नहीं हुई नियमित फैकल्टी भर्ती- डा. अमित व्यास

गुरुग्राम। हरियाणा के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की भारी कमी को लेकर डेमोक्रेटिक मेडिकल एसोसिएशन इंडिया (डीएमए) ने सरकार को चेताया है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास ने बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव और एनएमसी को ज्ञापन सौंपकर तुरंत नियमित भर्ती की मांग की है। यह ज्ञापन राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अमित व्यास, महासचिव डॉ. शुभ प्रताप सोलंकी, उपाध्यक्ष डॉ. भानु कुमार और महिला प्रकोष्ठ सचिव डॉ. प्रियांशु शर्मा की ओर से भेजा गया है।

ज्ञापन में कहा गया है कि डीएमईआर/यूएचएस रोहतक के पिछले चार साल में नियमित फैकल्टी भर्ती नहीं हुई। वर्ष 2022 की भर्ती अक्टूबर 2023 में पूरी हुई, जिससे कई एमडी, एमएस विशेषज्ञ निजी क्षेत्र और दूसरे राज्यों में चले गए। हाल ही में 750 अनुबंध पदों पर भर्ती निकली, लेकिन कम वेतन और असुरक्षा के कारण केवल 70-80 पद ही भरने की उम्मीद है। डा. अमित व्यास ने कहा कि पीजीआईएमएस रोहतक, केसीजीएमसी करनाल, बीपीएस खानपुर, मेवात मेडिकल कालेज में 30-40 प्रतिशत पद खाली हैं। एसएबीवी मेडिकल कालेज छायसा (फरीदाबाद) में 70 प्रतिशत पद खाली हैं।

भिवानी, कोरियावास (नारनौल) और कुटेल (करनाल) में स्थायी फैकल्टी लगभग शून्य है। डीएमए के अनुसार फैकल्टी संकट से एमबीबीएस और पीजी छात्रों की पढ़ाई, थीसिस-रिसर्च और क्लिनिकल ट्रेनिंग प्रभावित हो रही है। सुपर-स्पेशियलिटी सेवाएं और जटिल मरीजों का इलाज भी प्रभावित हो रहा है। एनएमसी मानकों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है, जिससे भविष्य में एमबीबीएस/पीजी सीटें बढऩे की बजाय घटने का खतरा है। डीएमए की ओर से मांग की गई है कि सभी स्वीकृत पदों पर समयबद्ध नियमित भर्ती की जाए। समान कार्य के लिए समान वेतन लागू हो।

प्राक्सी सर्वर लगाकर नकल करावाने वाले गिरोह के दो सरगना गिरफ्तार

नोएडा। उत्तर प्रदेश एसटीएफ की नोएडा यूनिट की टीम ने एसएससी परीक्षाओं में प्राक्सी सर्वर लगाकर नकल करावाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। नालेज पार्क कोतवाली क्षेत्र स्थित बालाजी डिजिटल जोन कंप्यूटर लैब में छापेमारी के बाद सात लोगों की गिरफ्तारी के बाद अब इस पूरे नेटवर्क को संचालित करने वाली कंपनी एएसएसईएसएस इंफ्रा के दो डायरेक्टरों को बीती रात को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ नोएडा यूनिट एसपी राजकुमार मिश्रा ने बताया कि जांच में पता चला कि परीक्षा केंद्रों को चिन्हित करना, उनका सिक्योरिटी आडिट करना और केंद्र संचालक व स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन कराना एएसएसईएसएस इंफ्रा की जिम्मेदारी थी। इसके एवज में संबंधित कंपनी द्वारा उसे तय दरों पर भुगतान किया जाता था।जांच में सामने आया है कि बालाजी डिजिटल जोन को एएसएसईएसएस इंफ्रा द्वारा ही एसएससी परीक्षा के लिए केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया था। इस केंद्र पर वर्ष 2025 से अब तक एसएससी की 16 परीक्षाएं आयोजित हो चुकी हैं, लेकिन इन परीक्षाओं को कराने के लिए एएसएसईएसएस इंफ्रा ने बालाजी डिजिटल जोन को निर्धारित शुल्क का भुगतान ही नहीं किया।बल्कि निर्धारित शुल्क न देकर एएसएसईएसएस इंफ्रा द्वारा परीक्षा केंद्र संचालक को सुरक्षा नियमों में अनदेखी करने की छूट दी जाती थी। इसके बदले केंद्र संचालक प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से पैसे लेकर नकल कराने की व्यवस्था कराता था। यह नेटवर्क उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली के दर्जनों संदिग्ध परीक्षा केंद्रों तक फैला हुआ है। अप्रैल-2026 में देहरादून के महादेव डिजिटल जोन में भी इसी तरह प्राक्सी सर्वर लगाकर नकल कराते पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि थाना कोतवाली देहरादून में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें मुख्य आरोपित के रूप में प्रदीप चौहान का नाम आया था। जानकारी होने के बावजूद ग्रेटर नोएडा स्थित प्रदीप चौहान की दूसरी लैब बालाजी डिजिटल जोन को फिर से परीक्षा केंद्र बना दिया।

स्कूल बस में शॉर्ट सर्किट से लगी आग

बागपत,एजेंसी। बागपत जिले के खेकड़ा क्षेत्र सुभानपुर गांव स्थित डीपीडब्लूएस स्कूल की एक बस में बुधवार दोपहर अचानक आग लग गई। जानकारी के अनुसार बस में उस समय पांच बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि समय रहते बच्चों और चालक की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया।

बताया गया कि छुट्टी के बाद बस बच्चों को घर छोड़ने जा रही थी। जैसे ही बस अब्दुलपुर गांव के पास पहुंची, अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया और बस धू-धू कर जलने लगी। इसी दौरान बस में सवार छात्र देवांश त्यागी ने आग लगने का एहसास होते ही शोर मचाया। छात्र की आवाज सुनते ही चालक ने तुरंत बस रोक दी और बिना देर किए सभी पांचों बच्चों को सुरक्षित नीचे उतारकर दूर खड़ा कर दिया। चालक की तत्परता और बच्चों की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी। स्कूल प्रबंधक राजकुमार त्यागी ने बताया कि बस में आग शॉर्ट

सर्किट के कारण लगी थी। हादसे की सूचना मिलते ही बच्चों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और उन्हें सुरक्षित घर ले गए। एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि बागपत के फायर सर्विस स्टेशन खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नूरपुर खालसा के पास स्कूल बस में लगी आग को फायर सर्विस स्टेशन खेकड़ा व सहायतार्थ फायर सर्विस स्टेशन यूनिट ट्रोनिका सिटी के द्वारा पूर्णरूप से बुझाया गया, अग्निकांड से कोई जनहानि नही है। सभी बच्चे सुरक्षित हैं।

पंजाबियों की विवेकशीलता की परीक्षा होंगे आसन्न चुनाव

अश्विनी कुमार

अगले वर्ष के आरंभ में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव राज्य के उथल-पुथल भरे राजनीतिक इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकते हैं। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, आगामी चुनाव राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के तौर-तरीकों और समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित कर सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार पांच प्रमुख राजनीतिक दल सत्ता के लिए चुनावी मैदान में आमने-सामने होंगे। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी यानी आप को चुनौती देने वाले चार विपक्षी दलों में 'वारिस पंजाब दे' भी शामिल है। यह एक नवोदित राजनीतिक संगठन है, जिसने अपने सुधारवादी तेवर और राजनीतिक बदलाव के वादे के कारण ग्रामीण सिख युवाओं के बीच उल्लेखनीय समर्थन हासिल किया है। यह स्थिति पारंपरिक राजनीतिक दलों के प्रति घटती जन-रुचि का भी संकेत देती है।

पंजाब की अस्मिता से जुड़े मुद्दों से काफी हद तक लोकप्रियता हासिल करने वाला यह नया राजनीतिक दल—अन्य दलों, विशेषकर अकाली दल, के मत प्रतिशत में सेंध लगा सकता है। हालांकि, संभवत: वह सत्तारूढ़ दल के लिए गंभीर चुनौती पेश करने की स्थिति में न हो। फिर भी, चुनावी मैदान में इसकी स्पष्ट उपस्थिति ने पंजाब के राजनीतिक संतुलन को प्रभावित किया है और उग्र राजनीति की वापसी को लेकर आशंकाओं को फिर से जन्म दिया है। राजनीतिक प्रासंगिकता पुन: हासिल करने का प्रयास कर रहे अकाली दल का सिमटता प्रभाव, तेजी से उभरती भाजपा और कांग्रेस द्वारा स्वयं को पहुंचाया गया राजनीतिक नुकसान—इन सभी ने मिलकर पंजाब की राजनीति का चेहरा बदला है। इसके साथ ही, अकाली दल और भाजपा के बीच संभावित गठबंधन चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बदल सकता है। यह गठबंधन आप के सामने प्रमुख चुनौती के रूप में उभर सकता है। इन परिस्थितियों में, खंडित जनादेश और उससे पैदा होने वाली राजनीतिक अस्थिरता की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। विभिन्न विकास सूचकांकों पर पंजाब की आ रही गिरावट को तब तक पलटा नहीं जा सकता, जब तक राज्य के पुनर्निर्माण और नवोदय के लिए महत्वपूर्ण नीतियों पर व्यापक राजनीतिक सहमति न बने। जमीनी परिस्थितियां और एक सुदृढ़ लोकतंत्र की आवश्यकताएं राजनीतिक संवाद में शालीनता तथा संबंधों में मर्यादा-सौहार्द की मांग करती हैं। राजनीतिक नेताओं के बीच संवाद के सौहार्दपूर्ण माध्यम बने रहना आवश्यक है, क्योंकि राज्य के विकास के लिए विवेकपूर्ण नीतियों पर व्यापक सहमति बनाने हेतु नेताओं के बीच सहयोग और सामंजस्य अनिवार्य है। सोशल मीडिया पर राजनीतिक नेताओं के बीच सार्वजनिक रूप से होने वाली कटु और अस्वस्थ बहसें, जो अब एक अंतहीन तमाशे का रूप ले चुकी हैं, उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता को कमजोर कर रही हैं। किसी की प्रतिष्ठा-गरिमा को कलंकित करना लोकतांत्रिक संवाद के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। हिंसक या भय उत्पन्न करने वाले स्वर में दिया गया वक्तव्य लोकतंत्र की उस सौम्यता और प्रभावकारी शक्ति को कमजोर करता है, जो राजनीतिक और सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने में उसकी केंद्रीय विशेषताएं हैं। इसलिए अब समय आ गया है कि सार्वजनिक संवाद का स्तर ऊंचा उठाया जाए।

एक जीवंत और समृद्ध राज्य के रूप में पंजाब के पुनरुत्थान के लिए उदार और विशाल हृदय वाले नेतृत्व की आवश्यकता है। आज पंजाब को ऐसा नेता चाहिए, जो स्वयं से ऊपर उठ सके, वंचित और हाशिये पर खड़े लोगों के प्रति करुणा और संवेदनशीलता को शासन का मूल भाव बना सके, सत्ता-प्राप्ति के आकर्षण का प्रतिरोध कर सके। हमें ऐसे नेता चाहिए, जो दमनकारी अधिकार को अपनी शक्ति न समझें और ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, जिनका नेतृत्व का दावा शक्ति-प्रदर्शन और समर्थकों के रूप में प्रस्तुत होने वाले सत्ता के दलालों की चाटुकारिता पर टिका हो। जनता के अन्याय और पीड़ा के प्रति उदासीन अहंकारी सत्ता का प्रतिरोध करना एक निर्विवाद नैतिक दायित्व है। लोकतंत्र अंतत: उन्हीं नेताओं के कारण टिकता है, जो शोषित और कमजोर लोगों की आंखों में छलकने से रह गए आंसुओं को देख सकें और उनकी दबी हुई आहों को सुन सकें।

पंजाब की वीर और जीवट जनता, जो गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेती है, अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ऐसे शासन की अधिकारी है, जिसकी नींव कानून व न्याय पर टिकी हो। एक जीवंत लोकतंत्र की वास्तविक कसौटी उसकी प्रक्रियाओं की शुचिता है—ऐसी प्रक्रियाएं, जो विचारों की स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के माध्यम से प्रेरणादायी नेतृत्व को जन्म दे सकें। ऐसा नेतृत्व 'चतुर व्यक्ति के अहंकार' पर नहीं, बल्कि मानवीय स्थिति की समग्र समझ पर आधारित होना चाहिए। हम जानते हैं कि लोकतंत्र हमारे समय के नैतिक प्रश्नों पर सार्वजनिक तर्क-विमर्श का नाम है। पंजाब जब अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुन: प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहा है, तब उसे ऐसे नेताओं के नेतृत्व वाली सरकार की आवश्यकता है, जिनमें 'दुस्साहसी आदर्शवाद' हो; ऐसे नेता जो ऐसी दिशा तय कर सकें, जिससे लोगों में आशा का संचार हो। साथ ही, रोजगार सृजन, नशे की समस्या से निपटने के लिए सार्थक नीतियों, राज्य की शक्ति के घोर दुरुपयोग और उच्च स्तर पर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश, राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन से जुड़े जटिल प्रश्नों पर विचारपूर्ण दृष्टिकोण, पर्यावरण संरक्षण तथा साझी विरासत पर आधारित सामाजिक सौहार्द के संरक्षण के माध्यम से उस आशा को ठोस रूप दिया जा सके। इन चुनौतियों के बावजूद, क्या हम यह आशा कर सकते हैं कि राज्य के विधानसभा चुनावों में राजनीतिक दल जातिवादी और सांप्रदायिक राजनीति से ऊपर उठेंगे? क्या वे ऐसे नेताओं को सामने ला सकते हैं, जिनके पास वह नैतिक विश्वसनीयता हो, जो एक गौरवशाली और वीर जनता से ईमानदारी से संवाद कर सकें और उसे सम्मानपूर्ण जीवन का अवसर देने का संकल्प प्रस्तुत कर सकें? या फिर पंजाब को ऐसे लोगों का बोझ उठाते रहना होगा, जिनके लिए राजनीति सही और गलत की किसी भावना से मुक्त होकर केवल सत्ता हासिल करने का साधन है? ये ऐसे प्रश्न हैं, जिनका सामना राज्य के राजनीतिक दलों और नेताओं को करना ही होगा। लोकतंत्र की सार्थकता तब सिद्ध होती है, जब एक जागरूक मतदाता उन लोगों को नेतृत्व सौंपने में सक्षम हो, जो नि:स्वार्थ भाव से प्रेरित हों और ऐसी राजनीति के प्रति प्रतिबद्ध हों, जिसमें मानवीय गरिमा और जनता के सम्मान को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो। उम्मीद की जानी चाहिए कि पंजाब ऐसी ऊर्जावान राजनीति का मार्गदर्शक बन सके—ऐसी राजनीति, जो जनता की इच्छाशक्ति को जाग्रत करे, हमारे संस्थापकों के आदर्शवाद से प्रेरणा ले और उस इच्छाशक्ति को एक नए सार्वजनिक उद्देश्य में परिणत करे। इसके लिए राजनीतिक स्पेक्ट्रम के विभिन्न हिस्सों से श्रेष्ठ नेतृत्व और प्रतिभाओं को साथ लाने तथा राज्य में परिवर्तनकारी नेतृत्व के विकास के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार करने की जरूरत होगी। अगले चुनाव में एक बार फिर पंजाब की जनता की सामूहिक विवेकशीलता की परीक्षा होगी।

दीनदयाल उपाध्याय के लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, वे इसे समाज और राष्ट्र की सेवा का साधन मानते थे। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय वे उसके संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका में आए और आगे चलकर पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री बने। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद संगठन को मजबूत करने और देशभर में उसका विस्तार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1967 में वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनकी सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक देन 'एकात्म मानववाद' मानी जाती है। उनका विचार था कि मनुष्य को केवल आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वित रूप है और उसके जीवन में भौतिक प्रगति के साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। इसी प्रकार व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए विकास का उद्देश्य केवल उत्पादन और आर्थिक आंकड़ों को बढ़ाना नहीं, मनुष्य और समाज के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक चिंतन भी इसी दृष्टि पर आधारित था। वे ऐसी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी विचार से जुड़ा उनका 'अंत्योदय' का सिद्धांत आज भी उनके चिंतन की प्रमुख पहचान है। उनका मानना था कि किसी भी विकास व्यवस्था की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि समाज के सबसे कमजोर और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कितना सुधार आया। इस दृष्टि से उनका चिंतन सामाजिक समावेशन और मानव-केंद्रित विकास की चर्चा में आज भी संदर्भित किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय केवल राजनेता और संगठनकर्ता ही नहीं, लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने लेखनी को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने 'राष्ट्रधर्म', 'पाञ्चजन्य' और 'स्वदेश' जैसे प्रकाशनों के माध्यम से राष्ट्र, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़े विषयों पर लिखा। उनके लेखन में सरल भाषा के साथ वैचारिक स्पष्टता दिखाई देती थी। उनका 'पॉलिटिकल डायरी' स्तंभ भी चर्चित रहा। पत्रकारिता को लेकर वे तथ्यपरकता और जिम्मेदारी पर जोर देते थे। उपलब्ध सामग्री के अनुसार, वे समाचारों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत करने के विरुद्ध थे और पत्रकार की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सादा था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन संगठन और सार्वजनिक कार्यों में लगाया। पद और प्रतिष्ठा के बावजूद उनका रहन-सहन सामान्य रहा। यही सादगी उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान बनी। उनके समर्थकों और सहयोगियों के संस्मरणों में उनके सहज व्यवहार, अनुशासन और कार्यकर्ताओं के साथ निकट संबंधों का उल्लेख मिलता है। वे संगठन को केवल पदों और संरचनाओं से नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से मजबूत करने में विश्वास रखते थे। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन बहुत लंबा नहीं था। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन के निकट एक रेलवे डिब्बे के पास उनका शव मिला। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों ने लंबे समय तक प्रश्न खड़े किए और यह घटना भारतीय राजनीतिक इतिहास की चर्चित घटनाओं में शामिल रही। उस समय वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा। उनका राजनीतिक जीवन और दर्शन भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा है। उनके विचारों से सहमत और असहमत दोनों पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके चिंतन को उसके मूल संदर्भ में समझा जाए। एकात्म मानववाद, अंत्योदय, विकेंद्रीकरण, स्वावलंबन, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र केंद्रित विकास उनके विचारों के प्रमुख पक्ष रहे। उनकी रचनाओं और भाषणों में राष्ट्र, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और सामाजिक जीवन पर व्यापक चिंतन मिलता है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति अपने विचार, अनुशासन और कर्म के बल पर सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है। उन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बजाय संगठन और सेवा से जोड़ने पर बल दिया। उनका एकात्म मानववाद व्यक्ति और समाज के संबंधों को समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास था जबकि अंत्योदय का विचार विकास के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर केंद्रित था। उनकी जयंती पर उन्हें याद करने का अर्थ केवल उनके नाम और योगदान का स्मरण करना नहीं बल्कि यह समझना भी है कि सार्वजनिक जीवन में विचार, सादगी, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का क्या महत्व है। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन भले अल्प रहा लेकिन उनके विचारों पर आज भी चर्चा होती है। यही किसी विचारक की सबसे बड़ी विरासत होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके विचार समाज को प्रश्न पूछने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे।

दीनदयाल उपाध्याय: साधारण जीवन, असाधारण विचार

योगेश कुमार गोयल

अंत्योदय दिवस/ दीनदयाल उपाध्याय जयंती (25 सितम्बर) पर विशेष

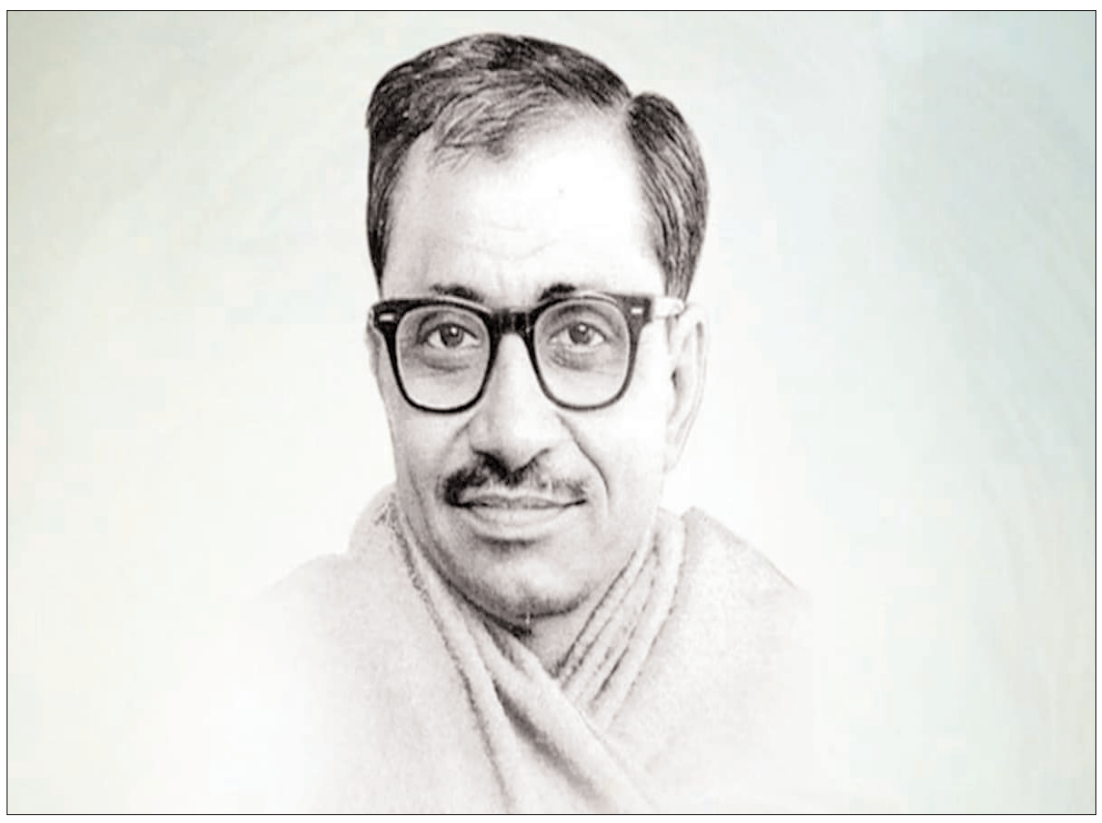

कुछ व्यक्तित्व अपने जीवन की लंबाई से नहीं बल्कि अपने विचारों की गहराई और कर्मों की व्यापकता से इतिहास में स्थान बनाते हैं। पं. दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही व्यक्तित्व थे। साधारण जीवन जीते हुए उन्होंने भारतीय राजनीति, समाज और अर्थचिंतन को भारतीय संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का प्रयास किया। उनका जीवन सादगी, अनुशासन, संगठन, राष्ट्रसेवा और वैचारिक प्रतिबद्धता का उदाहरण रहा। उनकी जयंती केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व को याद करने का अवसर नहीं बल्कि उनके विचारों और सार्वजनिक जीवन की भूमिका को समझने का अवसर भी है। 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला चंद्रभान गांव में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय का बचपन कठिन परिस्थितियों में बीता। कम उम्र में ही उन्होंने माता-पिता को खो दिया और उनका पालन-पोषण रिश्तेदारों के संरक्षण में हुआ। कठिनाइयों के बावजूद शिक्षा के प्रति उनका लगाव कम नहीं हुआ। वे पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे और विभिन्न स्तरों पर छात्रवृत्तियां प्राप्त करते रहे। पिलानी में शिक्षा के बाद उन्होंने कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज में अध्ययन किया। 1937 में छात्र जीवन के दौरान उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। आगे चलकर उन्होंने अपना जीवन पूर्णकालिक संगठनात्मक कार्य को समर्पित कर दिया।

दीनदयाल उपाध्याय के लिए राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का माध्यम नहीं थी, वे इसे समाज और राष्ट्र की सेवा का साधन मानते थे। 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना के समय वे उसके संगठन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका में आए और आगे चलकर पार्टी के अखिल भारतीय महामंत्री बने। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निधन के बाद संगठन को मजबूत करने और देशभर में उसका विस्तार करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1967 में वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उनकी सबसे महत्वपूर्ण वैचारिक देन 'एकात्म मानववाद' मानी जाती है। उनका विचार था कि मनुष्य को केवल आर्थिक आवश्यकताओं के आधार पर नहीं समझा जा सकता। मनुष्य शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा का समन्वित रूप है और उसके जीवन में भौतिक प्रगति के साथ नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास भी आवश्यक है। इसी प्रकार व्यक्ति समाज से अलग नहीं है। व्यक्ति, समाज और राष्ट्र एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसलिए विकास का उद्देश्य केवल उत्पादन और आर्थिक आंकड़ों को बढ़ाना नहीं, मनुष्य और समाज के संतुलित विकास को सुनिश्चित करना होना चाहिए। दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक चिंतन भी इसी दृष्टि पर आधारित था। वे ऐसी अर्थव्यवस्था के समर्थक थे, जिसमें विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी विचार से जुड़ा उनका 'अंत्योदय' का सिद्धांत आज भी उनके चिंतन की प्रमुख पहचान है। उनका मानना था कि किसी भी विकास व्यवस्था की सफलता का वास्तविक पैमाना यह होना चाहिए कि समाज के सबसे कमजोर और अंतिम व्यक्ति के जीवन में कितना सुधार आया। इस दृष्टि से उनका चिंतन सामाजिक समावेशन और मानव-केंद्रित विकास की चर्चा में आज भी संदर्भित किया जाता है। दीनदयाल उपाध्याय केवल राजनेता और संगठनकर्ता ही नहीं, लेखक और पत्रकार भी थे। उन्होंने लेखनी को सामाजिक जागरण का माध्यम बनाया। उन्होंने 'राष्ट्रधर्म', 'पाञ्चजन्य' और 'स्वदेश' जैसे प्रकाशनों के माध्यम से राष्ट्र, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति से जुड़े विषयों पर लिखा। उनके लेखन में सरल भाषा के साथ वैचारिक स्पष्टता दिखाई देती थी। उनका 'पॉलिटिकल डायरी' स्तंभ भी चर्चित रहा। पत्रकारिता को लेकर वे तथ्यपरकता और जिम्मेदारी पर जोर देते थे। उपलब्ध सामग्री के अनुसार, वे समाचारों को संदर्भ से काटकर प्रस्तुत करने के विरुद्ध थे और पत्रकार की जिम्मेदारी को महत्वपूर्ण मानते थे। उनका व्यक्तिगत जीवन अत्यंत सादा था। उन्होंने अपना अधिकांश जीवन संगठन और सार्वजनिक कार्यों में लगाया। पद और प्रतिष्ठा के बावजूद उनका रहन-सहन सामान्य रहा। यही सादगी उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान बनी। उनके समर्थकों और सहयोगियों के संस्मरणों में उनके सहज व्यवहार, अनुशासन और कार्यकर्ताओं के साथ निकट संबंधों का उल्लेख मिलता है। वे संगठन को केवल पदों और संरचनाओं से नहीं, समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से मजबूत करने में विश्वास रखते थे। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन बहुत लंबा नहीं था। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय रेलवे स्टेशन के निकट एक रेलवे डिब्बे के पास उनका शव मिला। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों ने लंबे समय तक प्रश्न खड़े किए और यह घटना भारतीय राजनीतिक इतिहास की चर्चित घटनाओं में शामिल रही। उस समय वे भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और उनके निधन से पार्टी को बड़ा झटका लगा। उनका राजनीतिक जीवन और दर्शन भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय रहा है। उनके विचारों से सहमत और असहमत दोनों पक्षों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि उनके चिंतन को उसके मूल संदर्भ में समझा जाए। एकात्म मानववाद, अंत्योदय, विकेंद्रीकरण, स्वावलंबन, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्र केंद्रित विकास उनके विचारों के प्रमुख पक्ष रहे। उनकी रचनाओं और भाषणों में राष्ट्र, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, लोकतंत्र और सामाजिक जीवन पर व्यापक चिंतन मिलता है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सीमित साधनों और कठिन परिस्थितियों में भी कोई व्यक्ति अपने विचार, अनुशासन और कर्म के बल पर सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकता है। उन्होंने राजनीति को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बजाय संगठन और सेवा से जोड़ने पर बल दिया। उनका एकात्म मानववाद व्यक्ति और समाज के संबंधों को समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास था जबकि अंत्योदय का विचार विकास के लाभ को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर केंद्रित था। उनकी जयंती पर उन्हें याद करने का अर्थ केवल उनके नाम और योगदान का स्मरण करना नहीं बल्कि यह समझना भी है कि सार्वजनिक जीवन में विचार, सादगी, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी का क्या महत्व है। दीनदयाल उपाध्याय का जीवन भले अल्प रहा लेकिन उनके विचारों पर आज भी चर्चा होती है। यही किसी विचारक की सबसे बड़ी विरासत होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके विचार समाज को प्रश्न पूछने, सोचने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहे।

विचार

कर्ज की वसूली हो लेकिन कानून की हद में

डॉ. सत्यवान सौरभ

कर्ज लेना एक आर्थिक अनुबंध है। कर्ज की राशि निर्धारित समय पर वापस न मिलने की स्थिति में बैंक या वित्तीय संस्था को अपनी बकाया राशि वसूलने का अधिकार है लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कर्ज की वसूली के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कानून, ऋण समझौते और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप होनी चाहिए। किसी व्यक्ति के ऊपर कर्ज बकाया होने का अर्थ यह नहीं है कि वित्तीय संस्था उसके साथ बलपूर्वक, अपमानजनक या मनमाने तरीके से व्यवहार कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय का हालिया फैसला इसी महत्वपूर्ण सिद्धांत को रेखांकित करता है। मामला उत्तर प्रदेश के हरि दत्ता शर्मा से संबंधित है। उन्होंने वर्ष 2019 में टाटा एसएफसी 407 ट्रक खरीदने के लिए चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड से वाहन ऋण लिया था। ट्रक उनके लिए केवल एक वाहन नहीं था बल्कि उनकी आजीविका का महत्वपूर्ण साधन था। ऋण की कुछ किस्तें बकाया होने के बाद वित्तीय संस्था और ऋणग्राही के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। शर्मा का आरोप था कि 9 अप्रैल 2023 की रात लगभग एक बजे कुछ लोग उनके वाहन को जबरन ले गए। आरोप यह भी था कि वाहन का स्टीयरिंग लॉक तोड़ा गया और निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया गया। इसके बाद वाहन को बेच दिया गया। मामला पहले उच्च न्यायालय पहुंचा, जहां याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद पीड़ित ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

हरि दत्ता शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2026 आईएनएससी 998 में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे मामले को केवल इस दृष्टि से नहीं देखा कि ऋण की किस्तें बकाया थीं। न्यायालय ने इस बात पर विशेष ध्यान दिया कि बकाया राशि की वसूली के लिए किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई गई। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऋणदाता को अपने वैध अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति है लेकिन अधिकार का इस्तेमाल कानून की सीमा के भीतर ही किया जा सकता है। किसी वित्तीय संस्था का ऋण वसूलने का अधिकार उसे बलपूर्वक वाहन छीनने या कानून अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं देता। ऋण की वसूली और व्यक्ति की गरिमा, दोनों के बीच कानूनी संतुलन आवश्यक है। इस मामले में ऋण समझौते में वाहन का कब्जा लेने से पहले सात दिन का नोटिस देने का प्रावधान था। न्यायालय ने पाया कि वाहन जब्त करने से पहले इस प्रावधान के अनुसार सात दिन का नोटिस नहीं दिया गया था। इसके अतिरिक्त वाहन को रात लगभग एक बजे ले जाने और स्टीयरिंग लॉक तोड़ने की घटना ने भी मामले को गंभीर बना दिया। न्यायालय ने इस प्रकार की कार्रवाई को विधिसम्मत और शांतिपूर्ण कब्जे की प्रक्रिया के अनुरूप नहीं माना। यहां यह समझना भी जरूरी है कि सात दिन का नोटिस हर प्रकार के वाहन ऋण की जब्ती के लिए सार्वभौमिक कानूनी नियम के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है। इस मामले में सात दिन की अवधि संबंधित ऋण समझौते में निर्धारित थी। इसलिए इस फैसले का सही अर्थ यही है कि यदि ऋण समझौते में किसी निश्चित प्रक्रिया या नोटिस का प्रावधान है तो वित्तीय संस्था को उसका पालन करना होगा। साथ ही लागू कानून और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों का भी पालन आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऋण वसूली के दौरान अनुचित दबाव, उत्पीड़न और बलप्रयोग के प्रश्न को भी गंभीरता से लिया। बैंक और वित्तीय संस्थाएं ऋण वसूली के लिए प्रतिनिधियों या वसूली एजेंटों की सहायता ले सकती हैं लेकिन ऐसे प्रतिनिधियों को कानून के दायरे में ही कार्य करना होगा। किसी ऋणग्राही को धमकाना, अपमानित करना, असामान्य समय पर परेशान करना या बलपूर्वक संपत्ति पर कब्जा करना वैध वसूली प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हो सकता। इस फैसले का एक महत्वपूर्ण पहलू व्यक्ति की आजीविका से जुड़ा है। यदि कोई ट्रक, टैक्सी, ऑटो या अन्य व्यावसायिक वाहन किसी व्यक्ति की आय का मुख्य साधन है तो उसे मनमाने तरीके से छीन लेने का प्रभाव केवल संपत्ति के नुकसान तक सीमित नहीं रहता। इससे व्यक्ति और उसके परिवार की आय प्रभावित हो सकती है। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 से जुड़े अधिकारों पर भी विचार किया। न्यायालय ने इस मामले में वाहन के आजीविका के साधन होने और उसके अनुचित तरीके से छीने जाने को गंभीरता से लिया। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रभावित ऋणग्राही को महत्वपूर्ण राहत भी दी। वित्तीय संस्था को दोनों ऋण खाते बंद करने, वाहन की बिक्री से प्राप्त 4.50 लाख रुपये की राशि वापस करने तथा उस राशि पर बिक्री की तारीख से भुगतान तक छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त मानसिक पीड़ा और आजीविका के नुकसान के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा तथा मुकदमे की लागत के रूप में 50 हजार रुपये देने का आदेश भी दिया गया।

एक नजर

हरदी में मनाया गया 11वां आयुर्वेद दिवस, स्वस्थ जीवनशैली में आयुर्वेद की उपयोगिता पर दिया जोर

सुपौल,एजेंसी। जिले के हरदी स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिर में बुधवार को 11वां आयुर्वेद दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय आयुष मिशन एवं जिला आयुष समिति, सुपौल के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने के साथ लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए आयुर्वेद के महत्व के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम की थीम 'एकीकृत स्वास्थ्य देखभाल, जीवन-शैली के लिए आयुर्वेद तथा आयुर्वेद में साक्ष्य, अनुसंधान एवं नवाचार' रखी गई थी। कार्यक्रम का उद्घाटन चिकित्सा प्रभारी ने फीता काटकर किया। इस दौरान आयुष्मान आरोग्य मंदिर हरदी के चिकित्सक डॉ. प्रवेश कुमार शर्मा, स्वास्थ्य विभाग के कर्मी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में वक्ताओं ने आयुर्वेद को भारतीय पारंपरिक चिकित्सा पद्धति की महत्वपूर्ण विरासत बताते हुए इसके वैज्ञानिक अनुसंधान और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ समन्वय पर चर्चा की। लोगों को दैनिक जीवन में दिनचर्या का पालन, संतुलित खान-पान तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में सरपंच कृष्णदेव, मुखिया विनय कुमार, ओमप्रकाश, सरपंच साह एवं शशिभूषण मंडल सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे। कार्यक्रम का मंच संचालन मंत्री गोपालकांति और रीता गुप्ता ने किया।

बाल विवाह की रोकथाम के लिए छात्राओं ने ली शपथ, बांटी गई एमएचएम किट

भागलपुर,एजेंसी। महिला एवं बाल विकास निगम, भागलपुर के जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वूमेन के तत्वावधान में बुधवार को सदर अस्पताल परिसर स्थित एएनएम ट्रेनिंग स्कूल में एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में एएनएम छात्राओं को माहवारी स्वच्छता, बाल विवाह की रोकथाम, साइबर सुरक्षा एवं वित्तीय साक्षरता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया, ताकि वे आगे चलकर समाज में जागरूकता की एक मजबूत कड़ी बन सकें। जिला मिशन समन्वयककार्यक्रम में जिला मिशन समन्वयक श्री तबरेज़ खान ने माहवारी स्वच्छता एवं स्वास्थ्य प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि माहवारी एक पूरी तरह प्राकृतिक प्रक्रिया है, इसलिए इसे लेकर किसी भी प्रकार की झिझक की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने छात्राओं को स्वच्छ उत्पादों के उपयोग, समय पर पैड बदलने, उनके उचित निपटान, हाथों की स्वच्छता और किसी भी असामान्य समस्या होने पर तुरंत स्वास्थ्यकर्मी से परामर्श लेने पर जोर दिया। जेंडर स्पेशलिस्टजेंडर स्पेशलिस्ट श्री विवेक कुमार ने बाल विवाह के स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने छात्राओं का आह्वान किया कि वे स्वयं जागरूक रहें और अपने परिवार व समुदाय में बाल विवाह जैसी कुप्रथा की रोकथाम के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं। वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अभिषेक सुमन ने छात्राओं को साइबर एवं डिजिटल अपराधों से बचाव के व्यावहारिक उपाय बताए। टीचर जूली कुमारी की सक्रिय सहभागिता में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्राओं ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने प्रश्न साझा किए। कार्यक्रम के अंत में सभी छात्राओं के बीच में एच एम किट का वितरण किया गया। साथ ही, बालिकाओं की शिक्षा और सुरक्षित भविष्य के निर्माण के संकल्प के साथ छात्राओं को बाल विवाह के खिलाफ सामूहिक शपथ दिलाई गई।

चुनाव आयोग के फैसलों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

पटना,एजेंसी। चुनाव आयोग के विभिन्न निर्णयों एवं आयोग के भीतर दर्ज आपत्तियों के विरोध में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमिटी द्वारा बुधवार को पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव के नेतृत्व में आक्रोश मार्च सह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन किया एवं इस्तीफे की मांग की। इस अवसर पर अनुशासन समिति के अध्यक्ष कपिलदेव प्रसाद यादव ने कहा कि चुनाव आयोग सरकार और सत्तारूढ़ दल के हाथों की कठपुतली की तरह काम कर रहा है। पार्टी का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक निष्पक्ष संवैधानिक संस्था के प्रमुख की भूमिका के बजाय सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त स्वयं को संस्था से ऊपर मानकर काम कर रहे हैं और अन्य चुनाव आयुक्तों की आपत्तियों एवं असहमतियों को पर्याप्त महत्व नहीं दिया जा रहा है। पार्टी ने कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया में आम मतदाताओं के नाम प्रभावित होते हैं अथवा उनके मताधिकार पर सवाल खड़े होते हैं, तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले लगभग 10 महीनों में आयोग के विभिन्न कदमों एवं आदेशों पर 14 बार रिकॉर्ड पर आपत्ति दर्ज की है।

बिहार कैबिनेट: 24 प्रस्तावों पर मुहर, बेगूसराय में दिनकर और पटना में मां सीता महिला विवि को मंजूरी

पटना,एजेंसी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की जयंती पर बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय और पटना में मां सीता महिला विश्वविद्यालय की स्थापना को स्वीकृति दी। दिनकर विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई।

कैबिनेट ने पशुपालकों के लिए मुख्यमंत्री गो-धन विकास ऋण योजना को मंजूरी देते हुए बैंक ऋण के ब्याज पर 100 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया। इसके तहत लाभुकों को केवल मूलधन चुकाना होगा। योजना के लिए 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। उन्नत नस्ल की तीन गाय या दो भैंस के माध्यम से दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और पशुपालकों की आय में वृद्धि पर जोर दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की स्थापना को भी मंजूरी दी गई। परियोजना में 500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। इससे नवादा के साथ नालंदा, शेखपुरा और जमुई के किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। बैठक में सात निश्चय-3 के तहत कोसी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के अधीन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में डेयरी विकास योजनाओं को भी मंजूरी मिली। करीब 126.07 करोड़ रुपये की लागत से दही प्लांट, प्रीमियम आइसक्रीम प्लांट, मिल्क चिलिंग प्लांट सहित अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जिला पुलिस, रेल पुलिस, मद्यनिषेध और राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ लोक भवन

से संबंधित उपकरणों की खरीद के लिए 336.85 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। केंद्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 50 ड्रोन खरीदने को भी मंजूरी मिली है। इन पर 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इनका उपयोग भीड़ नियंत्रण, नदी क्षेत्र में अभियान, नक्सल विरोधी अभियान और आपदा प्रबंधन में किया जाएगा।

कैबिनेट ने नगर निगम पटना को कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए पूर्व में दिए गए 41.0041 करोड़ रुपये के ऋण को अनुदान के रूप में समायोजित करने का निर्णय लिया। राज्य के 12 चिकित्सा संस्थानों में ई-सुश्रुत एनएक्स एप्लीकेशन लागू करने की योजना को भी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार बॉयलर (जांच, न्यायनिर्णयन एवं अपील) नियमावली, 2026 को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में उच्च शिक्षा, पशुपालन, डेयरी, चीनी उद्योग, पुलिस आधुनिकीकरण और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े प्रस्ताव शामिल हैं।

कैबिनेट के फैसले बिहार के विकास की नई दिशा तय करेंगे : नीरज शर्मा

पटना। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 24 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगना साबित करता है कि बिहार अब शिक्षा, कृषि, पशुपालन, कानून-व्यवस्था और औद्योगिक निवेश हर मोर्चे पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। यह फैसले कागजी घोषणा नहीं, बल्कि जमीन पर बदलाव लाने वाले ठोस कदम हैं।

भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने प्रमुख निर्णयों का उल्लेख करते हुए कहा कि बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय और पटना में माता सीता विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा को गांव-गांव तक पहुंचाने और बेटियों को उच्च शिक्षा का नया केंद्र देने का ऐतिहासिक कदम है। रामधारी सिंह दिनकर की साहित्यिक-सांस्कृतिक विरासत को संस्थागत रूप मिलेगा, वहीं माता सीता विश्वविद्यालय महिला सशक्तिकरण को नई ऊंचाई देगा। दोनों विश्वविद्यालयों के लिए प्रारंभिक 15-15 करोड़ रुपये की स्वीकृति इसी दूरदर्शिता को दर्शाती है। नवादा के वारिसलीगंज में नई चीनी मिल की मंजूरी से नवादा, नालंदा, शेखपुरा और जमुई के हजारों गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री गौधन विकास ऋण योजना के अंतर्गत पशुपालकों को गाय-भैंस खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और कोसी क्षेत्र में 126 करोड़ रुपये के डेयरी विकास प्रस्ताव से दूध उत्पादन, प्रसंस्करण और किसानों की आय बढ़ेगी। पुलिस आधुनिकीकरण के तहत 50 आधुनिक ड्रोन और 336.85 करोड़ रुपये के उपकरण उपस्कर की स्वीकृति कानून-व्यवस्था को और मजबूत करेगी। ये ड्रोन भीड़ प्रबंधन, नक्सल विरोधी अभियान, नदी किनारे के ऑपरेशन और आपदा प्रबंधन में काम आएंगे। पूर्व विद्युत बोर्ड कर्मचारियों के लिए 757.63 करोड़ रुपये की स्वीकृति सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण है। जल संसाधन विकास निगम के गठन और स्वास्थ्य संस्थानों में ई-सुश्रुत एनएक्स लागू करने से शासन अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनेगा। भाजपा प्रवक्ता नीरज कुमार शर्मा ने कहा कि ये फैसले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की उस सोच का परिणाम हैं, जिसमें शिक्षा, किसान, पशुपालक, युवा और सुरक्षा सभी को साथ लेकर चलने का संकल्प है। सम्राट सरकार विकास को नारे नहीं, परिणाम बना रही है।

दिशा की बैठक में विकास योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को प्रगति तेज करने का निर्देश

सुपौल। समाहरणालय स्थित लहटन चौधरी सभागार में बुधवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सांसद सह दिशा समिति के अध्यक्ष दिलेश्वर कामैत की अध्यक्षता में हुई। बैठक में जिले में संचालित विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा में पूरा कराने का निर्देश दिया।

बैठक में निर्मली विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव, पिपरा विधायक रामविलास कामत, त्रिवेणीगंज विधायक सोनम रानी, जिला परिषद अध्यक्ष कमला देवी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, सभी प्रखंड प्रमुख एवं मनोनीत सदस्य उपस्थित रहे। जिलाधिकारी सावन कुमार, उप विकास आयुक्त इन्द्रवीर कुमार, अपर समाहर्ता सचिदानंद सुमन, सिविल सर्जन सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भी बैठक में मौजूद थे। रोजगार सृजन से संबंधित योजना की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में मानव दिवस सृजन का लक्ष्य 17 लाख 19 हजार 552 निर्धारित किया गया है। इसके विरुद्ध अब तक 10 लाख 27 हजार 210 मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है, जो निर्धारित लक्ष्य का 59.74 प्रतिशत है। योजना के तहत क्रियान्वित कुल योजनाओं में से 93.14 प्रतिशत योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। शेष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की समीक्षा में बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में अब तक कुल 25,991 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। लाभुकों को दूसरी एवं तीसरी किस्त की राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। अधिकारियों को शेष अपूर्ण आवासों का निर्माण जल्द पूरा कराने का निर्देश दिया गया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 21 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के लक्ष्य के विरुद्ध 19 का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि दो का निर्माण जारी है। जिले में लक्षित 174 कचरा प्रसंस्करण इकाइयों में से 172 का निर्माण पूरा किया जा चुका है।

दो किराना दुकानों से करीब 2 किलो गांजा बरामद, महिला समेत दो गिरफ्तार

भागलपुर,एजेंसी। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार जिले के युवाओं को नशे के चंगुल से बचाने और मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे विशेष महाअभियान 'स्वस्थ युवा स्वस्थ भागलपुर' के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कजरैली थाना क्षेत्र में लगातार दो दिनों तक चलाए गए छापामारी अभियान में पुलिस ने दो अलग-अलग किराना दुकानों से कुल 1.980 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक महिला समेत दो धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी विधि-व्यवस्था, भागलपुर ने बुधवार को प्रेस वार्ता के दौरान इस पूरी कार्रवाई की विस्तृत जानकारी साझा की।

एसडीपीओ ने बताया कि बीते रात्रि कजरैली पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बेलगच्छी गोराचौकी निवासी कृष्णनंद मंडल अपनी किराना दुकान की आड़ में अवैध मादक पदार्थों की खरीद-बिक्री कर रहा है। सूचना के सत्यापन के लिए नगर पुलिस अधीक्षक की निगरानी और एसडीपीओ विधि-व्यवस्था और कजरैली थानाध्यक्ष के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान में विधिवत तलाशी ली, जहां से 650 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मौके से अभियुक्त कृष्णनंद मंडल (पिता- दिनेश मंडल) को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी अभियान के क्रम में अगले ही दिन यानी बुधवार को पुलिस को पुनः गुप्त सूचना मिली कि नीमा गोराचौकी स्थित

एक अन्य किराना दुकान में अवैध मादक पदार्थ का संग्रह किया गया है। गठित पुलिस टीम ने तत्काल साकिन-नीमा गौराचौकी स्थित ऊषा देवी की किराना दुकान पर छापेमारी की। तलाशी के दौरान दुकान से भारी मात्रा में 1.330 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी महिला ऊषा देवी (पति- बिट्टू मंडल) को विधिवत गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों सफल छापों को अंजाम देने वाली टीम में कजरैली थानाध्यक्ष सह पुअनि गौतम कुमार, पुअनि उमेश शुक्ला, सअनि सुनील कुमार, महिला सिपाही चंदा कुमारी, सिपाही हरिचरण कुमार और कजरैली थाने के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। एसडीपीओ विधि-व्यवस्था ने बताया कि दोनों गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और पुलिस इनसे पूछताछ कर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों का पता लगा रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले नशा तस्करों के खिलाफ यह अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों के औचक निरीक्षण में बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति पर जोर

सुपौल,एजेंसी। आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में पारदर्शिता, बच्चों की नियमित उपस्थिति और गुणवत्तापूर्ण सेवाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बुधवार को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आईसीडीएस अंजू कुमारी ने बाल विकास परियोजना किशनपुर के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 15, 16, 17 एवं 23 का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में केंद्र संख्या 15 पर 28, केंद्र संख्या 16 पर 21, केंद्र संख्या 17 पर 18 तथा केंद्र संख्या 23 पर 21 बच्चे सेविका-सहायिका के साथ उपस्थित पाए गए।

निरीक्षण के दौरान जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने संबंधित सेविका एवं सहायिका को निर्देश दिया कि केंद्रों पर नामांकित सभी बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बच्चों को निर्धारित मेनू के अनुसार पोषाहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण स्कूल पूर्व शिक्षा (ईसीसीई) प्रदान करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था को दुरुस्त रखने का निर्देश दिया। साथ ही टीएचआर (टेक होम राशन) का एफआरएस के माध्यम से पात्र लाभुकों के बीच शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने को कहा गया। औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए बच्चों को लेकर भी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने गंभीरता दिखाई। उन्होंने बाल विकास परियोजना

पदाधिकारी, किशनपुर को निर्देश दिया कि संबंधित सेविका-सहायिका एवं महिला पर्यवेक्षिका से निरीक्षण की तिथि को अनुपस्थित बच्चों के संबंध में कारण-पृच्छा की जाए। साथ ही नियमानुसार अनुपस्थित बच्चों से संबंधित पोषाहार राशि की कटौती की कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इसकी जानकारी जिला प्रोग्राम कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा।

इसके अलावा महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रत्येक संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आठ पात्र लाभार्थियों तथा मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तीन पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अंजू कुमारी ने महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, किशनपुर को केंद्रों का नियमित निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति, पोषाहार वितरण, स्कूल पूर्व शिक्षा सहित अन्य निर्धारित सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन लगातार सुनिश्चित किया जाए। निरीक्षण के बाद सेविका-सहायिका द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रगति प्रतिवेदन को जिला प्रोग्राम कार्यालय, आईसीडीएस, सुपौल में उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में लापरवाही, बच्चों की अनावश्यक अनुपस्थिति, पोषाहार वितरण में अनियमितता अथवा विभागीय निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

चलती ट्रेन में गूंजी किलकारी, सीवान की महिला यात्री ने बेटे को दिया जन्म

सीवान,एजेंसी। जनसेवा एक्सप्रेस में सफर कर रही एक महिला ने बुधवार को मैरवा-सीवान के बीच बच्चे को जन्म दिया। महिला अकेले यात्रा कर रही थी और प्रसव के बाद उसे तत्काल चिकित्सीय सहायता की जरूरत थी। सूचना मिलते ही आरपीएफ दरौंधा चौकी के जवान सक्रिय हुए और ट्रेन के दुरौंधा स्टेशन पहुंचते ही जच्चा-बच्चा को सुरक्षित उतारकर अस्पताल पहुंचाया।

चिकित्सकों के अनुसार मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। रेसुब के अनुसार रेसुब कंट्रोल वाराणसी से सूचना मिली कि ट्रेन संख्या 14618 जनसेवा एक्सप्रेस के नौवें कोच में महिला का प्रसव हुआ है। महिला अकेले यात्रा कर रही है। सूचना मिलते ही एएसआई ग्यास सरवर, कांस्टेबल रामजी यादव और प्वाइंट्समैन स्ट्रेचर लेकर दरौंधा स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या तीन पर पहुंचे। स्टेशन मास्टर ने तत्काल एंबुलेंस को सूचना दी। ट्रेन के कोच संख्या 216198/सी में महिला ने बेटे को जन्म दिया था। सहयात्रियों की मदद से महिला और नवजात को ट्रेन से उतारा गया। इसी कोच में अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहे धर्मेंद्र पासवान ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए अपनी यात्रा रोक दी और महिला की मदद के लिए दुरौंधा स्टेशन पर उतर गए। उन्होंने चिकित्सीय सहायता के लिए रेलवे हेल्पलाइन 139 पर दो बार शिकायत भी दर्ज कराई। एंबुलेंस की मदद से जच्चा-बच्चा को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुरौंधा के महिला वार्ड में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने दोनों को स्वस्थ बताया। सहयात्री धर्मेंद्र पासवान ने बताया

कि महिला का प्रसव मैरवा-सीवान के बीच हुआ था और कोच में मौजूद महिलाओं ने प्रसव के दौरान उसकी मदद की थी। महिला ने अपना नाम लाली कुमारी, पति ऋषिदेव, निवासी गोठेला, थाना मधेपुरा, जिला मधेपुरा बताया। उसके पास ब्यास से सहरसा जंक्शन का सामान्य टिकट भी मिला। रेसुब ने महिला के पति के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर घटना की जानकारी दी। बाद में महिला के मौसा मनोज सादा और मौसी ललिता देवी भी अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने रेसुब के जवानों और सहयोग करने वाले सहयात्री धर्मेंद्र पासवान के प्रति आभार जताया।

एक नजर

टी-20 मुंबई लीग में नवी मुंबई की एंट्री, छह साल के लिए 106.88 करोड़ रुपये का करार

मुंबई,एजेंसी। टी-20 मुंबई लीग के विस्तार को नई रफ्तार देते हुए मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने नवी मुंबई के लिए नौवीं फ्रेंचाइजी का ऐलान किया है। एस्पेक्ट्स स्पोर्ट्स ने छह साल के लिए 106.88 करोड़ रुपये की बोली के साथ यह फ्रेंचाइजी हासिल की है, जिसमें पहले सत्र के लिए 12.21 करोड़ रुपये की राशि तय की गई है। नवी मुंबई के जुड़ने से लीग का दायरा मुंबई के पारंपरिक क्रिकेट केंद्रों से आगे बढ़ेगा और क्षेत्र के उभरते खिलाड़ियों को बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। एमसीए अध्यक्ष अजिंक्य नाइक ने कहा कि नवी मुंबई तक लीग का विस्तार मुंबई के क्रिकेट पारिस्थितिकी तंत्र के हर हिस्से तक खेल को पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि नई फ्रेंचाइजी से युवा खिलाड़ियों के लिए अवसर बढ़ेंगे। टी-20 मुंबई लीग गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन राजदीप गुप्ता ने कहा कि नौवीं फ्रेंचाइजी का जुड़ना लीग के विकास में नया अध्याय है। उनके मुताबिक, फ्रेंचाइजी की संख्या बढ़ने से लीग के लिए अधिक मजबूत और टिकाऊ क्रिकेट इकोसिस्टम तैयार करने में मदद मिलेगी। एस्पेक्ट ग्लोबल वेंचर्स की कार्यकारी चेयरपर्सन और एस्पेक्ट्स स्पोर्ट्स की मालिक अक्ष कंबोज ने नवी मुंबई का प्रतिनिधित्व करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि कंपनी खेलों में खिलाड़ियों और समुदायों के लिए अवसर तैयार करने तथा भारत में खेल के विकास में योगदान देने की दिशा में काम करना चाहती है। टी-20 मुंबई लीग के 'फेस ऑफ द लीग' विश्व कप विजेता भारतीय कप्तान रोहित शर्मा हैं। 2026 संस्करण में सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, शार्दुल ठाकुर, सरफराज खान और तुषार देशपांडे जैसे खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। नई फ्रेंचाइजी के जुड़ने से लीग का विस्तार और मुंबई क्षेत्र की उभरती क्रिकेट प्रतिभाओं के लिए मंच और व्यापक होने की उम्मीद है।

एशियाई खेल : सतनाम-सलमान और बलराज पंवार रोइंग के फाइनल में पहुंचे

आइची-नगोया। भारतीय रोइंग खिलाड़ियों सतनाम सिंह, सलमान खान और बलराज पंवार ने बुधवार को एशियाई खेलों में अपने-अपने मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह बना ली। सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स स्पर्धा के फाइनल ए में प्रवेश किया। दोनों ने अपनी हीट में 6 मिनट 15.63 सेकंड का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया। दोनों हीट के संयुक्त परिणाम में वे चौथे स्थान पर रहे। डबल स्कल्स का फाइनल गुरुवार को होगा। पुरुष सिंगल स्कल्स स्पर्धा में बलराज पंवार ने भी फाइनल ए में जगह बनाई। उन्होंने अपनी हीट में 6 मिनट 52.84 सेकंड का समय निकालकर तीसरा स्थान हासिल किया। दोनों हीट के संयुक्त परिणाम में बलराज चौथे स्थान पर रहे और अब उनके पास पदक जीतने का मौका होगा। भारतीय रोइंग टीम इन क्वालीफाइंग प्रदर्शनों के बाद फाइनल में भी मजबूत प्रदर्शन के साथ पदक हासिल करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा भारतीय पुरुष कयाक चार 500 मीटर टीम ने भी फाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया। हर्षवर्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल नाओचा सिंह ओइनाम और अरुण सिंह की टीम ने अपनी हीट में 1 मिनट 29.447 सेकंड का समय लेकर तीसरा स्थान हासिल किया। वह शीर्ष पर रहने वाली चीन की टीम से 5.594 सेकंड पीछे रही। एशियाई खेलों के चौथे दिन भारतीय दल के सामने कई अहम मुकाबले हैं और कई खिलाड़ियों से पदक की उम्मीद है। ओलंपिक पदक विजेता मीराबाई चानू और मनु भाकर भी भारतीय अभियान में अहम भूमिका निभाएंगी। भारत ने अब तक एशियाई खेलों में सात पदक जीते हैं, जिनमें एक स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य पदक शामिल हैं।

एशियाई खेल : मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल के फाइनल में बनाई जगह

आइची-नगोया। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता निशानेबाज मनु भाकर ने बुधवार को एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में जगह बना ली। मनु ने क्वालीफिकेशन में 579 अंक हासिल कर तीसरा स्थान प्राप्त किया। पेरिस ओलंपिक में दो कांस्य पदक जीतने वाली मनु ने क्वालीफिकेशन में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया और शीर्ष तीन में रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। भारत की ईशा सिंह 572 अंक के साथ 15वें स्थान पर रहीं और फाइनल में जगह नहीं बना सकीं। वहीं, सुरुचि सिंह ने 568 अंक के साथ 26वां स्थान हासिल किया। भारत को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में वियतनाम से पदक के लिए कड़े मुकाबले में हार मिली। दोनों टीमों के 1719 अंक बराबर रहे, लेकिन इनर-10 के आधार पर भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने एशियाई खेलों में शूटिंग से अब तक पांच पदक जीते हैं, जिनमें चार रजत और एक कांस्य पदक शामिल है। हालांकि, भारतीय निशानेबाजों को अब भी स्वर्ण पदक का इंतजार है।

मीराबाई चानू ने जीता एशियाई खेलों का अपना पहला पदक, 49 किग्रा वर्ग में हासिल किया रजत

आइची-नगोया,एजेंसी। ओलंपिक पदक विजेता और तीन बार की राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता मीराबाई चानू ने बुधवार को एशियाई खेलों में अपना पहला पदक जीत लिया। उन्होंने आइची-नगोया एशियाई खेलों की महिला 49 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक हासिल किया। चानू ने प्रतियोगिता में कुल 198 किग्रा वजन उठाया। स्नैच वर्ग में उन्होंने अपने तीनों प्रयास सफलतापूर्वक पूरे किए और क्रमश: 83, 85 और 87 किग्रा वजन उठाया। क्लीन एंड जर्क में चानू ने 107 किग्रा के सफल प्रयास के साथ शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे प्रयास में 111 किग्रा वजन सफलतापूर्वक उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किग्रा रहा। उत्तर कोरिया की री सोंग गुम ने 215 किग्रा के कुल वजन के साथ स्वर्ण पदक जीता। मीराबाई चानू को 198 किग्रा के साथ रजत पदक मिला, जबकि विजायना ने कांस्य पदक अपने नाम किया।

यह पदक चानू के लिए खास है। 2023 हांगझोउ एशियाई खेलों में चोट के कारण उन्हें क्लीन एंड जर्क का अंतिम प्रयास छोड़ना पड़ा था और वह चौथे स्थान पर रही थीं। इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियाई खेलों में अपना पहला पदक हासिल किया। टोक्यो 2020 ओलंपिक की रजत पदक विजेता चानू ने हाल ही में संपन्न राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। एशियाई खेलों में रजत के साथ उन्होंने अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करियर में एक और बड़ी उपलब्धि जोड़ ली है। कर्णम मल्लेश्वरी के बाद मीराबाई चानू ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व चैंपियनशिप, एशियाई चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप—इन सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बन गई हैं।

भारत के खिलाफ पहले वनडे के लिए वेस्टइंडीज टीम तिरुवनंतपुरम पहुंची

तिरुवनंतपुरम। भारत के खिलाफ 27 सितंबर से शुरु होने वाले पहले एकदिवसीय सीरीज के लिए वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम बुधवार सुबह तिरुवनंतपुरम पहुंच गई। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार दोपहर दो बजे शुरू होगा। शाई होप की कप्तानी वाली वेस्टइंडीज टीम तीन मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत का सामना करेगी। श्रृंखला का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को गुवाहाटी में और तीसरा मैच तीन अक्टूबर को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा।

क्रिकेट वेस्टइंडीज ने भारत दौरे के लिए तीन एकदिवसीय और पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की टीमों की घोषणा की है। यह दौरा 27 सितंबर से 18 अक्टूबर तक आठ शहरों में खेला जाएगा। वेस्टइंडीज की एकदिवसीय टीम में जॉन कैंपबेल की वापसी हुई है। वह हैमस्ट्रिंग चोट के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम दो एकदिवसीय मैचों में नहीं खेल सके थे। एकेम ऑगस्टे की जगह ज्वेल एंड्रयू को टीम में शामिल किया गया है। ऑगस्टे अगस्त में सर्जरी के बाद अभी पुनर्वास की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। शिमरॉन हेटमायर न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम दो एकदिवसीय मैचों में खेले थे। उन्हें कैरेबियन प्रीमियर लीग के बाद अतिरिक्त आराम दिए जाने के कारण वह भारत के खिलाफ एकदिवसीय श्रृंखला में टीम के साथ नहीं होंगे और टी20 अंतरराष्ट्रीय श्रृंखला के लिए जुड़ेंगे। भारत के खिलाफ पहले दो एकदिवसीय मैचों के साथ आईसीसी पुरुष 50 ओवर विश्व कप का मौजूदा क्वालीफिकेशन चक्र भी समाप्त होगा। हालांकि, परिणाम चाहे जो भी हों, वेस्टइंडीज अंक तालिका में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को पीछे नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे में उसे अगले साल की शुरुआत में होने वाले क्वालीफिकेशन टूर्नामेंट के जरिए विश्व कप में जगह बनाने की कोशिश करनी होगी। भारत की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे, जबकि केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। रोहित शर्मा और विराट कोहली को 15 सदस्यीय टीम में शामिल किया गया है। यह श्रृंखला भारत के लिए 2027 एकदिवसीय विश्व कप की तैयारियों के बीच खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखने का महत्वपूर्ण अवसर होगी। रवींद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की भी भारत की एकदिवसीय टीम में वापसी हुई है। वहीं, जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी और पंजाब के ऑलराउंडर नमन धीर को पहली बार एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया है।

एशियाई खेल: पुरुष स्कीट टीम ने जीता कांस्य, अनंतजीत नरूका व्यक्तिगत फाइनल में पहुंचे

आइची-नगोया। भारतीय निशानेबाजों अनंतजीत सिंह नरूका, मेराज अहमद खान और भवतेघ सिंह गिल की पुरुष स्कीट टीम ने बुधवार को एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीत लिया। भारतीय टीम ने 346 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। कजाकिस्तान के साथ समान अंक रहने के बाद शूट-ऑफ में जीत दर्ज कर भारत ने कांस्य पदक अपने नाम किया। अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष स्कीट की व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भी जगह बना ली है। उन्होंने क्वालीफिकेशन में शानदार प्रदर्शन किया और अब वह दोपहर 12:30 बजे भारतीय समयानुसार होने वाले फाइनल में पदक के लिए चुनौती पेश करेंगे। भारत के लिए शूटिंग में यह दिन बेहद सफल रहा। इससे पहले भारतीय महिला स्कीट टीम ने भी कांस्य पदक जीता। रायजा ढिल्लों, पारिनाज धालीवाल और महेश्वरी चौहान की टीम ने 331 अंक के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। चीन ने स्वर्ण और कजाकिस्तान ने रजत पदक जीता।

दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत फाइनल में जगह बनाई, लेकिन 181.1 अंक के साथ पांचवें स्थान पर रहीं। सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह क्वालीफिकेशन के बाद फाइनल में जगह नहीं बना सकीं। सॉफ्ट टेनिस में जय मीना ने फिलीपींस के शेरविन नुगुइट को पुरुष एकल के रोमांचक क्वार्टर फाइनल में हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अंतिम चार में पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों का पदक पक्का होने के कारण जय ने भारत के लिए इस खेल में एशियाई खेलों का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। रोइंग में बलराज पंवार ने पुरुष सिंगल स्कल्स के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। उन्होंने अपनी हीट में तीसरा स्थान हासिल किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स में अपनी हीट में दूसरा स्थान हासिल कर फाइनल में जगह बनाई। कैनो स्प्रिंट में हर्षवर्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल नाओचा सिंह ओइनाम और अरुण सिंह की पुरुष कयाक चार 500 मीटर टीम ने पहली हीट में तीसरा स्थान हासिल कर फाइनल में प्रवेश किया। मेघा प्रदीप ने महिलाओं की कैनो एकल 200 मीटर के सेमीफाइनल में जगह बनाई, जबकि पार्वती गीता और फाइरेम्बम सोनिया देवी महिलाओं की कयाक डबल 500 मीटर के सेमीफाइनल में पहुंचीं।

एशियाई खेल: जय मीना ने रचा इतिहास, सॉफ्ट टेनिस में भारत का पहला पदक पक्का

आइची-नगोया,एजेंसी। भारतीय सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी जय मीना ने एशियाई खेलों में इतिहास रचते हुए पुरुष एकल के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही भारत का सॉफ्ट टेनिस में एशियाई खेलों का पहला पदक भी पक्का हो गया है। जय मीना ने बुधवार को रोमांचक क्वार्टर फाइनल में फिलीपींस के शेरविन नुगुइट को 4-3 से हराया। उतार-चढ़ाव से भरे मुकाबले में जय ने 0-4, 4-2, 2-4, 5-3, 2-4, 7-5 से जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही जय का पदक पक्का हो गया है, क्योंकि अंतिम चार में पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को पदक मिलता है।

अब जय की नजरें सेमीफाइनल पर हैं, जहां जीत उन्हें स्वर्ण पदक मुकाबले में पहुंचा देगी। आइची-नगोया में उनका शानदार अभियान भारत के लिए सॉफ्ट टेनिस में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गया है। जय का सॉफ्ट टेनिस से जुड़ाव लगभग संयोग से हुआ। बचपन में उनकी रुचि क्रिकेट में थी और वह क्रिकेटर बनना चाहते थे। देवास के पायनियर पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के दौरान उन्होंने पहली बार सॉफ्ट टेनिस कोर्ट देखा। शुरुआत में वह खिलाड़ियों को देखने और बॉल बॉय के तौर पर मदद करने लगे, लेकिन धीरे-धीरे खुद इस खेल को खेलने लगे। स्कूल और जिला स्तर से आगे बढ़ते हुए उन्होंने राज्य और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पहचान बनाई। 14 साल की उम्र में ही उन्होंने सॉफ्ट टेनिस के गढ़ जापान में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया। जय ने 2022 में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुष एकल का स्वर्ण पदक जीतकर भारत के शीर्ष सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ियों में अपनी जगह मजबूत की।

उन्होंने पुरुष टीम और युगल स्पर्धाओं में भी मध्य प्रदेश की पदक जीतने वाली टीमों में योगदान दिया। 2025 में वह पुरुष एकल में राष्ट्रीय चैंपियन बने। 2022 के हांगझोउ एशियाई खेलों में जय ने पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया था और पुरुष टीम स्पर्धा में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके बाद 2024 में आध्या तिवारी के साथ जोड़ी बनाकर उन्होंने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए इस प्रतियोगिता में पहला पदक हासिल किया। 2025 की एशियाई सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में जय पुरुष एकल के सेमीफाइनल में पहुंचकर कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने इस प्रतियोगिता में कुल चार पदक अपने नाम किए। आइची-नगोया एशियाई खेलों में यह उनका तीसरा एशियाई खेल है। इससे पहले वह जकार्ता 2018 और हांगझोउ 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जय की उपलब्धियों में 2024 विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में मिश्रित युगल कांस्य, 2025 एशियाई सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल, मिश्रित युगल, पुरुष टीम और मिश्रित टीम के कांस्य पदक शामिल हैं। उन्होंने 2026 सुनचांग ओपन में पुरुष एकल कांस्य और 2024 कोरिया कप में मिश्रित युगल कांस्य भी जीता है।

इसके अलावा जय ने पहले दक्षिण एशियाई सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीते हैं। दूसरे इंडिया इंटरनेशनल सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में भी उन्होंने पुरुष एकल, पुरुष युगल और मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक हासिल किए। देवास के एक स्कूल कोर्ट से शुरू हुआ जय मीना का सफर अब विश्व और एशियाई स्तर पर ऐतिहासिक पदकों तक पहुंच चुका है। एशियाई खेलों में भारत का पहला सॉफ्ट टेनिस पदक पक्का करना उनके करियर की एक और बड़ी उपलब्धि है।

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने घोषित की 16 सदस्यीय टीम, सैंटनर कप्तान

ऑकलैंड,एजेंसी। न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ आगामी पांच मैचों की टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। सफेद गेंद के कप्तान मिशेल सैंटनर टीम की अगुआई करेंगे। टीम में सात तेज गेंदबाजों को शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, पांच मैचों की सीरीज की शुरुआत 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में होगी। 11 दिनों के दौरान चार शहरों में मुकाबले खेले जाएंगे। यह सीरीज भारत के न्यूजीलैंड दौरे का हिस्सा है, जिसमें पांच एकदिवसीय और दो टेस्ट मैच भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, इस दौरे के लिए अब तक 76,000 से अधिक टिकट बिक चुके हैं। न्यूजीलैंड की टीम में इस साल आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत से हारकर उपविजेता रहने वाली टीम के 13 खिलाड़ी शामिल हैं।

स्पिन ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल और तेज गेंदबाज एडम मिल्न चोट के कारण विश्व कप से बाहर रहने के बाद टीम में लौटे हैं। 34 वर्षीय मिल्न ने अब तक 243 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें 56 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले शामिल हैं। उन्होंने एक साल से अधिक समय बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी की है। मिल्न के साथ लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, काइल जैमीसन और जैकब डफी जैसे अनुभवी तेज गेंदबाज हैं, जबकि जैक फाउल्क्स और नाथन स्मिथ को भी टीम में जगह मिली है। हालांकि, बल्लेबाजी ऑलराउंडर रचिन रवींद्र चोट के कारण टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। पिछले सप्ताह एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान उनके दाहिने कंधे का जोड़ खिसक गया था। उनके करीब छह सप्ताह तक पुनर्वास की उम्मीद है और वह चार नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में शुरू होने वाली एकदिवसीय सीरीज से वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं।

न्यूजीलैंड ने टी20 विश्व कप के बाद पहली बार आक्रामक सलामी बल्लेबाजों टिम सेफर्ट और फिन एलन को शीर्ष क्रम में फिर से साथ रखा है। विश्व कप के सेमीफाइनल में एलन ने ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 33 गेंदों में नाबाद शतक लगाया था, जबकि सेफर्ट ने 33 गेंदों में 58 रन बनाकर न्यूजीलैंड को नौ विकेट से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। सेफर्ट को द हंड्रेड में टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया था। उन्होंने 394 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 168 रहा। फाइनल में उन्होंने 38 गेंदों में 72 रन की मैच विजयी पारी खेली थी। तेज गेंदबाज बेन सीयर्स को टखने की चोट से उबरने के कारण चयन के लिए विचार में नहीं रखा गया।

भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम:

मिशेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, बेवन जैकब्स, काइल जैमीसन, एडम मिल्न, डैरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, नाथन स्मिथ।

एशियाई खेल टेबल टेनिस : मानुष-दीया और हरमीत-यशस्विनी की जोड़ी मिश्रित युगल स्पर्धा के तीसरे दौर में

आइची-नगोया। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ियों मानुष शाह-दीया चितले और हरमीत देसाई-यशस्विनी घोरपड़े ने बुधवार को एशियाई खेलों की मिश्रित युगल स्पर्धा के दूसरे दौर में अपने-अपने मुकाबले जीतकर अगले चरण में जगह बनाई। मानुष और दीया ने श्रीलंका के चानुल कुलप्पुवावडु और बिमांडी स्वर्णा को 3-0 से हराया। भारतीय जोड़ी ने मुकाबला 11-8, 12-10, 11-4 से अपने नाम किया। वहीं, हरमीत देसाई और यशस्विनी घोरपड़े ने मालदीव के मोहम्मद इस्माइल और फातिमाथ अली को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। कैनो स्प्रिंट में भारत की पार्वती गीता और फाइरेम्बम सोनिया देवी ने महिलाओं की कयाक डबल 500 मीटर स्पर्धा के सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारतीय जोड़ी हीट ए में 2 मिनट 02.538 सेकंड के समय के साथ अंतिम स्थान पर रही और शीर्ष नाव से 14.820 सेकंड पीछे रही। शीर्ष तीन नावों ने सीधे फाइनल ए के लिए क्वालीफाई किया।

रोइंग में बलराज पंवार ने पुरुष सिंगल स्कल्स की हीट में तीसरा स्थान हासिल किया और दोनों हीट के संयुक्त परिणाम में चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। सतनाम सिंह और सलमान खान ने पुरुष डबल स्कल्स की हीट में दूसरा स्थान हासिल किया और संयुक्त परिणाम में चौथे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई। कैनो स्प्रिंट में हर्षवर्धन शक्तावत, वरिंदर सिंह, एल नाओचा सिंह ओइनाम और अरुण सिंह की भारतीय टीम ने पुरुष कयाक चार 500 मीटर की हीट में तीसरा स्थान हासिल कर फाइनल के लिए क्वालीफाई किया। मेघा प्रदीप ने महिलाओं की कैनो एकल 200 मीटर हीट में पांचवां स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में जगह बनाई। शूटिंग में मनु भाकर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाई। उन्होंने क्वालीफिकेशन में 579-20एक्स के स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। सुरुचि इंदर सिंह और ईशा सिंह फाइनल में जगह बनाने से चूक गईं। तैराकी में बेनेडिक्टन बेनिस्टन पुरुष 100 मीटर बटरफ्लाई की हीट में चौथे और कुल मिलाकर 13वें स्थान पर रहे, जबकि साजन प्रकाश ने शुरुआत नहीं की। दोनों फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर सके। वहीं, वेदांत माधवन पुरुष 200 मीटर फ्रीस्टाइल की अपनी हीट में छठे और अनीश सुनील चौथे स्थान पर रहे। इन दोनों के फाइनल में पहुंचने की स्थिति परिणाम पर निर्भर है। रोइंग में जसविंदर सिंह और नितिन कुमार ने पुरुष पेयर हीट में चौथा स्थान हासिल किया और फाइनल बी के लिए क्वालीफाई किया। भारतीय महिला फोर टीम में गुरबानी कौर, अलीना एंटो, तेंदेथोई हाओबिजाम और पूनम ने भी हीट में हिस्सा लिया। आगे भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम सेमीफाइनल में चीन का सामना करेगी। भारत पहले ही पदक पक्का कर चुका है और अब उसकी नजरें फाइनल में जगह बनाने पर होंगी। वुशु खिलाड़ी रोशिबिना देवी भी बुधवार को अपनी स्पर्धा के फाइनल में जगह बनाने के लक्ष्य के साथ उतरेंगी।

एक नजर

ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप के पास जोरदार धमाके

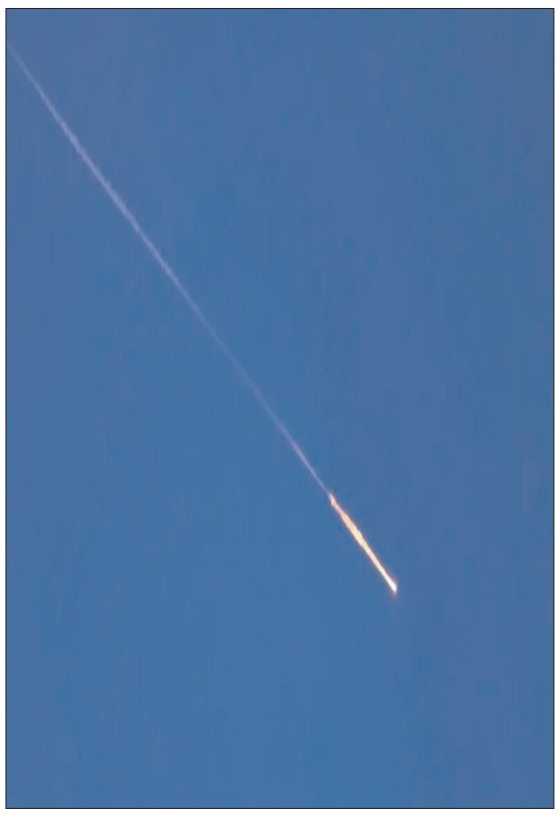

तेहरान,एजेंसी। ईरान के रणनीतिक केशम द्वीप के पास जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। यह आवाज समुद्र की तरफ से आई। फिलहाल द्वीप के भू-भाग पर किसी मिसाइल या रॉकेट के गिरने की पुष्टि नहीं हुई है। यह रणनीतिक इलाका होर्मुज जलडमरूमध्य के पास स्थित है। अनादोलू की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सरकारी मीडिया और इरना न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। इरना ने साफ किया है कि यह आवाज जमीन की तरफ से नहीं, बल्कि समुद्र की तरफ से आई थी। एजेंसी ने कहा कि द्वीप पर कोई रॉकेट या मिसाइल नहीं गिरी। स्थानीय अधिकारियों ने धमाके की असल वजह पर अब तक कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है। होर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित केशम द्वीप खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है। यह घटना होर्मुज में लगातार चल रहे समुद्री और सैन्य तनाव के बीच हुई है। यह ऊर्जा के परिवहन का एक अहम रास्ता है और ईरान से जुड़े संघर्षों का मुख्य केंद्र रहा है। इससे पहले 16 सितंबर को भी केशम द्वीप के तटवर्ती इलाके में धमाके हो चुके हैं।

ईरान के अधिकारी मिले अमेरिका के विशेष दूत विटकॉफ से, अगली बैठक जल्द : ट्रंप

न्यूयॉर्क,एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि ईरान के अधिकारियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के साथ तीन घंटे तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक और बैठक होगी। विटकॉफ ने कहा कि बैठक अच्छी रही। यह जून में स्विट्जरलैंड में अमेरिकी उप राष्ट्रपति जेडी वेंस की ईरानी प्रतिनिधिमंडल के साथ समझौता ज्ञापन पर सहमति के लिए हुई पहली मुलाकात है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने पुष्टि की कि विटकॉफ के साथ हुई बैठक में उनके विदेशमंत्री अब्बास अरागची शामिल हुए और कतर के राजनयिकों ने इसमें मध्यस्थता की। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी संकेत दिया कि ईरान एक सप्ताह के भीतर होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य और आर्थिक दबाव को कम करने पर तैयार हो जाए तो बात बन जाएगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य खोलने के लिए सात कठिन शर्तें रखी थीं। इनमें सभी मोर्चों पर अमेरिकी युद्ध को खत्म करना और प्रतिबंधों सहित ईरान के खिलाफ सभी आक्रामक कार्रवाई को रोकना शामिल था। इस बीच एक ईरानी अधिकारी ने जापानी समाचार एजेंसी क्योडो को बताया कि यह नया रुख उन शर्तों में से कुछ में ढील देने से जुड़ा होगा। अधिकारी ने दावा किया कि इस रुख को ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई और देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने मंजूरी दे चुके हैं। हालांकि, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स (आईआरजीसी) के करीबी प्रमुख ईरानी मीडिया ने किसी भी नए रुख को अपनाने से इनकार किया है।

नेपाल को पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका देगा 31 मिलियन डॉलर की अतिरिक्त सहायता

काठमांडू। अमेरिका ने नेपाल में बाढ़ के बाद पुनर्स्थापना और पुनर्निर्माण के लिए अतिरिक्त 31 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता देने की घोषणा की है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की राजनीतिक मामलों की उपसचिव एलिसन हुकर ने न्यूयॉर्क में नेपाल के विदेशमंत्री शिशिर खनाल के साथ मुलाकात के दौरान यह घोषणा की। बैठक में हुकर ने नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों और अब भी लापता करीब 70 अमेरिकी नागरिकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। अमेरिका ने प्रभावित क्षेत्रों में परिवहन बुनियादी ढांचे की बहाली और क्षेत्रीय संपर्क मजबूत करने के लिए 10 मिलियन डॉलर मूल्य के स्थायी तथा जरूरत के अनुसार स्थापित किए जा सकने वाले पुल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इन पुलों की खरीद अमेरिकी कंपनियों से की जाएगी। इसी तरह, प्रभावित समुदायों के लिए पेयजल, स्वच्छता एवं साफ-सफाई, आश्रय, संरक्षण, आजीविका और सर्दियों के लिए आवश्यक सहायता समेत विभिन्न क्षेत्रों में अतिरिक्त 8 मिलियन डॉलर उपलब्ध कराने की योजना है। बाढ़ के बाद आपदा प्रबंधन को और प्रभावी बनाने के लिए अमेरिका में निर्मित ड्रोन उपलब्ध कराने पर 13 मिलियन डॉलर खर्च करने की योजना भी घोषित की गई है। इस घोषणा के साथ नेपाल में बाढ़ राहत और पुनर्स्थापना प्रयासों के लिए अमेरिका की कुल सहायता 36 मिलियन डॉलर से अधिक हो गई है। अमेरिकी दूतावास ने यह जानकारी दी। अमेरिका ने नेपाल सरकार के साथ मिलकर जरूरतों का आकलन करने और आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता भी जताई है।

यूएन महासभा में पेज़ेश्कियन का ट्रंप को जवाब, बोले- ईरान आतंकवादी नहीं, आतंकवाद का पीड़ित

न्यूयॉर्क,एजेंसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक दिन पहले दिए भाषण का तीखा जवाब देते हुए कहा कि ईरान आतंकवाद का समर्थक नहीं, बल्कि खुद आतंकवाद का शिकार रहा है। उन्होंने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान पर हुए हमलों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनका देश अपनी रक्षा कर रहा है और दबाव के आगे झुकने वाला नहीं है। पेज़ेश्कियन ने कहा कि जिस युद्ध के दौरान ईरान में एक स्कूल पर हमला हुआ, उसमें बच्चे मारे गए। उन्होंने दावा किया कि इस हमले में अमेरिका और इजराइल के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। संयुक्त राष्ट्र की हालिया जांच के अनुसार, मिनाब में एक प्राथमिक स्कूल पर फरवरी में हुए हमले में 150 से अधिक लोग मारे गए थे, जिनमें 120 बच्चे शामिल थे। हालांकि अमेरिका ने हमले की जिम्मेदारी से इनकार किया।

ईरानी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश परमाणु तकनीक का इस्तेमाल ऊर्जा और विकास के लिए करना चाहता है, न कि परमाणु हथियार बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि ईरान शांतिपूर्ण परमाणु तकनीक के अपने अधिकार को नहीं छोड़ेगा, लेकिन परमाणु हथियार हासिल करने का उसका कोई इरादा नहीं है। पेज़ेश्कियन ने अमेरिका से बातचीत और कूटनीति के लिए ईरान की तत्परता भी जताई। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि वार्ता धमकी या सैन्य दबाव की भाषा में नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद ईरान अपना सिर नहीं झुकाएगा। होर्मुज जलडमरूमध्य का जिक्र करते हुए पेज़ेश्कियन ने कहा कि ईरान ऐसे हालात स्वीकार नहीं कर सकता, जहां दूसरे देश इस जलमार्ग से अपने हित साधें और उसी रास्ते का इस्तेमाल ईरान पर दबाव डालने के लिए भी करें। फिलिस्तीन के मुद्दे पर उन्होंने इसे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की अंतरात्मा पर 'खुला घाव' बताया और कहा कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति फिलिस्तीन के साथ न्याय के बिना संभव नहीं है। पेज़ेश्कियन ने अंत में कहा कि ईरान ने युद्ध शुरू नहीं किया और वह बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए पीछे नहीं हटेगा। उनके संबोधन के दौरान अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के सभागार से बाहर चले जाने की बात भी सामने आई।

लीबिया और सूडान में हथियारों की अवैध आपूर्ति के मामले में ब्रिटिश ब्रोकर को 16 साल की सजा

लंदन। दक्षिण सूडान और लीबिया में हथियारों की अवैध आपूर्ति से जुड़े मामलों में ब्रिटेन की एक अदालत ने बुधवार को हथियार ब्रोकर डेविड ग्रीनहाल्घ को 16 साल जेल की सजा सुनाई है। 68 वर्षीय ग्रीनहाल्घ को जून में बिना लाइसेंस हथियारों की आपूर्ति से जुड़े 10 मामलों में दोषी ठहराया गया था। लंदन की साउथवार्क क्राउन कोर्ट में सुनवाई के दौरान सामने आया कि 2009 से 2016 के बीच ग्रीनहाल्घ ने पूर्व सोवियत सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों के अलावा एके-47 राइफल, टैंक और बड़ी मात्रा में गोला-बारूद के सौदों में भूमिका निभाई थी। ग्रीनहाल्घ के साथ ग्रीस के नागरिक 48 वर्षीय क्रिस्टोस फार्माकिस को भी नौ मामलों में दोषी पाया गया।

हालांकि, उसका मुकदमा उसकी अनुपस्थिति में चला। न्यायाधीश सैली-ऐन हेल्स ने दोनों को 16-16 वर्ष की सजा सुनाते हुए कहा कि दोनों ने हथियार निर्यात प्रतिबंधों को दरकिनार कर भारी मुनाफे के लिए हथियारों की बिक्री कराने की बार-बार कोशिश की। अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपों में एक मामला हथियारों की वास्तविक आपूर्ति से जुड़ा था। इसमें यूक्रेन की पूर्व सोवियत एस-125 पेचोरा मिसाइल प्रणाली दक्षिण सूडान को बेचने का सौदा शामिल था। अभियोजन ने कहा कि दोनों आरोपियों के दक्षिण सूडान के वरिष्ठ अधिकारियों से करीबी संपर्क थे। अभियोजन पक्ष ने बताया कि उस समय दक्षिण सूडान अभी औपचारिक रूप से सूडान का हिस्सा था और 2011 में स्वतंत्र होने से पहले उस क्षेत्र पर ब्रिटिश हथियार प्रतिबंध लागू था। ग्रीनहाल्घ और फार्माकिस ने ईरान, इराक और सीरिया को भी हथियार उपलब्ध कराने की योजनाएं बनाईं, जिन पर संबंधित समय में हथियार प्रतिबंध लागू थे। फार्माकिस की गिरफ्तारी 2016 में हुई। जांच तब आगे बढ़ी, जब उसने सरकारी वित्त पोषित ग्रेटर लंदन एंटरप्राइज में अपनी नौकरी से जुड़े ईमेल खाते का इस्तेमाल निजी हथियार सौदों के लिए किया। इसी दौरान अधिकारियों को 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद लीबिया को लड़ाकू विमान और अन्य हथियार बेचने की योजनाओं से जुड़े दस्तावेज मिले।

संरा महासभा में तुर्किये के दृष्टिकोण का विरोध, इजराइल का बहिर्गमन

न्यूयॉर्क। तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में एक कड़े भाषण में गाजा और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। इससे नाराज इजराइली प्रतिनिधिमंडल बहिर्गमन (वॉकआउट) कर गया। मगर फिलिस्तीनी प्रतिनिधियों ने तालियां बजाईं। एर्दोगन ने गाजा में इजराइल के लगातार हो रहे युद्ध अपराधों और कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों में रहने वाले लोगों द्वारा किए जा रहे हमलों और हिंसा के बढ़ने का मुद्दा उठाया। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, ''अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन से हमने युद्धविराम में योगदान दिया। लेकिन इस तथाकथित युद्धविराम के बावजूद गाजा में 1,300 से ज्यादा आम नागरिकों की हत्या कर दी गई है।'' उन्होंने कहा कि हालांकि हमास और अन्य फिलिस्तीनी समूहों ने अक्टूबर के युद्धविराम समझौते के दूसरे चरण को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इजराइल गाजा में अपनी कार्रवाई बंद नहीं कर रहा है।

एर्दोगन ने कहा, ''हम एक ऐसी नरसंहार वाली मानसिकता का सामना कर रहे हैं जिसका खून-खराबे से कभी मन नहीं भरता। इंसानियत, दया या जमीर रखने वाला कोई भी व्यक्ति इससे आंखें नहीं मूंद सकता।'' एर्दोगन ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वह संघर्ष वाले इलाकों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में नाकाम रहा है। उन्होंने कहा, 'इक्यासी (81) साल पहले, दुनिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र बनाया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि यूएन अपना फर्ज निभाने में नाकाम रहा है। एर्दोगन ने कहा कि यूएन बेअसर हो गया है और फिलिस्तीन, लेबनान और सूडान में उसकी हालत बहुत खराब हो गई है। एर्दोगन ने दुनिया के नेताओं की यूएन बैठक में फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास की गैर मौजूदगी का भी जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका ने फिलिस्तीनी नेता को देश में आने के लिए वीजा देने से मना कर दिया था। ऐसा दो साल में दूसरी बार हुआ है। एर्दोगन ने कहा, ''भले ही राष्ट्रपति अब्बास यहां हमारे साथ मौजूद नहीं हैं, लेकिन हम फिलिस्तीन को आजाद और संप्रभु देश मानते हैं और उसकी आवाज उठाते रहेंगे।' तुर्किये के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर रूस के युद्ध का भी जिक्र किया और कहा कि अब इस संघर्ष को खत्म करने का समय आ गया है।

गुटेरेस ने नेपाल त्रासदी को जलवायु परिवर्तन के खतरे का वास्तविक रूप बताया

काठमांडू,एजेंसी। संयुक्त राष्ट्रसंघ महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि तीन वर्ष पहले नेपाल के सगरमाथा (माउंट एवरेस्ट) क्षेत्र से उन्होंने जलवायु परिवर्तन के खतरे को लेकर जो चेतावनी दी थी, नेपाल में हाल की घटनाओं ने उसके वास्तविक रूप को सामने ला दिया है। संयुक्त राष्ट्रसंघ की 81वीं महासभा को मंगलवार सुबह संबोधित करते हुए गुटेरेस ने कहा कि तीन वर्ष पहले उन्होंने नेपाल के हिमालय से दुनिया को चेतावनी दी थी कि 'दुनिया की छत' खतरे में है और बर्फ बेहद तेजी से पिघल रही है।

उन्होंने कहा, 'तीन वर्ष पहले नेपाल के हिमालय से मैंने चेतावनी दी थी कि दुनिया की छत गिर रही है। मैंने बर्फ के बेहद तेजी से पिघलने को लेकर खतरे की घंटी बजाई थी। कुछ लोगों ने इसे खतरे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना कहकर खारिज कर दिया था। लेकिन नेपाल की मौजूदा दुखद घटनाओं ने दिखा दिया है कि इसके गंभीर प्रभाव हमारी सोच से कहीं पहले सामने आ रहे हैं और उनका दायरा भी लगातार बढ़ रहा है। गुटेरेस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का खतरा अब वास्तविकता बन चुका है और दुनिया इसे अपनी आंखों के सामने देख रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की सबसे बड़ी कीमत कमजोर देशों को चुकानी पड़ रही है, जबकि उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने महासभा में कहा कि जलवायु परिवर्तन की कीमत प्रदूषण फैलाने वालों को चुकानी होगी और इसके प्रभाव से प्रभावित कमजोर देशों को न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने जलवायु न्याय की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि विकसित और समृद्ध देशों को इसकी कीमत चुकानी होगी।

गुटेरेस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए उपलब्ध वित्तीय संसाधन बेहद कम हैं। उन्होंने 'हानि एवं क्षति कोष में मौजूद राशि को शर्मनाक रूप से कम बताया। उन्होंने कहा, 'इसमें बेहद कम पैसा है। इसमें पर्याप्त धनराशि होनी चाहिए। अब और लूट एवं शोषण नहीं होना चाहिए। यूएन महासचिव ने विकसित देशों से जलवायु वित्त के संबंध में अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि विकसित देशों को अनुकूलन वित्त को तीन गुना करना चाहिए और 'हानि एवं क्षति कोष' को बड़े स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करने में सक्षम बनाना चाहिए। गुटेरेस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का खतरा सबसे अधिक कमजोर लोगों के लिए है। उन्होंने कहा कि आज एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के भविष्य का इस्तेमाल कर रही है और एक समूह इससे लाभ कमा रहा है, जबकि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम जिम्मेदार लोग ही इसके सबसे पहले और सबसे गंभीर प्रभावों का सामना कर रहे हैं।

ईरान ने रद की तेहरान से बगदाद और मस्कट जाने वाली उड़ानें, टर्किश एयरलाइंस की सेवा मार्च तक बंद

तेहरान,एजेंसी। ईरान ने बुधवार आधी रात से तेहरान से बगदाद और मस्कट जाने वाली उड़ानें रद कर दी हैं। ऐसा क्षेत्रीय एयरपोर्ट्स पर अमेरिकी दबाव बढ़ने के कारण किया गया है। इस दबाव का मकसद ईरान की एयरलाइंस को इंटरनेशनल ऑपरेशन्स से अलग-थलग करना है। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन ने कहा कि इराकी और ओमान की राजधानियों के लिए उड़ानें 23 सितंबर को स्थानीय समयानुसार रात 12 बजे से रद कर दी जाएंगी।

ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने मंगलवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने बताया कि ईरानी अधिकारी बगदाद जाने वाली उड़ानों को नजफ की ओर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तस्नीम ने कहा कि बाकी इंटरनेशनल उड़ानें, जिनमें इस्तांबुल के लिए सेवाएं भी शामिल हैं, तय समय के अनुसार चलेंगी। इराक सिविल एविएशन अथॉरिटी के सूत्रों ने बताया कि इराकी सरकार ने अधिकारियों को बुधवार आधी रात से बगदाद के लिए ईरानी उड़ानें रोकने का आदेश दिया था। ईरान के सिविल एविएशन ऑर्गनाइजेशन के प्रवक्ता माजिद अखवन ने भी कहा कि मस्कट एयरपोर्ट अब ईरानी यात्रियों को स्वीकार नहीं करेगा और तेहरान इन प्रतिबंधों को लेकर ओमान के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। इन उड़ानों का रद होना ईरान के एविएशन सेक्टर के खिलाफ वाशिंगटन के तेज किए गए अभियान का शुरुआती नतीजा है।

अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने सोमवार को कहा कि ईरानी एयरलाइंस 23 सितंबर से इंटरनेशनल ऑपरेशन्स से प्रभावी रूप से बाहर हो जाएंगी। उन्होंने एयरपोर्ट्स, फ्यूल सप्लायर्स, ग्राउंड-हैंडलिंग फर्मों और अन्य कंपनियों को चेतावनी दी कि प्रतिबंधों का सामना कर रही ईरानी एयरलाइंस को सेवाएं देने से उन पर अमेरिकी जुर्माना लग सकता है। ईरानी यात्रियों के लिए इराक अहम है, क्योंकि लाखों लोग देश के शिया पवित्र स्थलों, खासकर नजफ और कर्बला की यात्रा करते हैं। उधर टर्किश एयरलाइंस ने मार्च 2027 तक ईरान के लिए अपनी सभी उड़ानें रोक दी हैं।

न्यूयॉर्क पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति, समझौता न होने पर ट्रंप ने इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म करने की धमकी दी

न्यूयॉर्क,एजेंसी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान मंगलवार (स्थानीय समय) को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के 81वें सत्र में हिस्सा लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए। वह युद्ध पर ईरान का पक्ष रखेंगे और तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक समाधान की कोशिश करेंगे। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चेतावनी दे चुके हैं कि अगर समझौता नहीं हुआ तो वे इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म कर देंगे। इरना और अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, पेजेश्कियान बुधवार सुबह महासभा के सत्र को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि वह इस दौरान संघर्ष, कथित अपराधों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं पर ईरान के अविश्वास जैसे मुद्दों पर तेहरान का पक्ष रखेंगे। न्यूयॉर्क रवाना होने से पहले पेजेश्कियान ने कहा 'हम अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ईरान का पक्ष मजबूती से रखेंगे।

संयुक्त राष्ट्र में हम जो मुद्दे उठाएंगे, उनमें ईरानी जनता की दयनीय स्थिति, हुए अपराध और पैदा हुए अविश्वास को उजागर करना शामिल है। हम कई बार बातचीत की मेज पर बैठे और समझौतों पर हस्ताक्षर किए, लेकिन दुर्भाग्य से, पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे वादे पूरे नहीं किए गए और समझौतों को पैरों तले रौंद दिया गया।' पेजेश्कियान का आगमन ट्रंप के संयुक्त राष्ट्र महासभा संबोधन के ठीक बाद हुआ, जिसमें उन्होंने ईरान के साथ समझौता करने या इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करने के बीच एक विकल्प पेश किया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर संघर्ष खत्म करने के लिए कोई समझौता नहीं हुआ तो वे इस्लामिक रिपब्लिक को खत्म कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें बड़ा फैसला लेना है। ट्रंप ने कहा कि ईरान इंतजार कर रहा है कि अमेरिकी मध्यावधि चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव का तेहरान के प्रति उनके नजरिए पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, 'ईरान के मामले में मैं चुनाव को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देता और न ही दूंगा।

यह मेरे दिमाग में भी नहीं आता। मेरे लिए सिर्फ एक ही बात मायने रखती है कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं होंगे। 'रिपोर्ट के अनुसार, जब ट्रंप ने तेहरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियानों के बारे में बोलना शुरू किया तो ईरानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने वॉकआउट करदिया। इरना के अनुसार, रवानगी से पहले पेजेश्कियान को पहले उप राष्ट्रपति मोहम्मद रजा अरेफ, सुप्रीम लीडर के कार्यालय में अंतरराष्ट्रीय मामलों के डिप्टी होज्जतोलइस्लाम वालमोस्लेमिन मोहसेन कोमी और ईरानी कैबिनेट के सदस्यों ने आधिकारिक तौर पर विदाई दी। न्यूयॉर्क में प्रवास के दौरान, पेजेश्कियान वहां मौजूद राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। साथ ही अमेरिका में रहने वाले पढ़े-लिखे ईरानियों, अमेरिकी विशिष्ट लोगों और थिंक टैंक के साथ अलग-अलग बातचीत भी करेंगे।

2017 के पहले प्रदेश का माहौल खराब कर रखा था सपा के गुंडों ने, बेटियों को करते थे परेशान : योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर,एजेंसी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा को लेकर समाजवादी पार्टी (सपा) पर एक बार फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में ऐसी स्थिति थी कि कहावत चल पड़ी थी, 'देख सपाई, बिटिया घबराई।' अभिभावक बेटियों की पढ़ाई और सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। तत्कालीन सरकार के गुंडों ने माहौल खराब कर रखा था। कई जिलों में बेटियों की पढ़ाई संकट में थी। सपा के शोहदे उन्हें परेशान करते थे, जबरन उठा ले जाते थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में गुंडागर्दी, जमीन पर कब्जे और अराजकता का माहौल था। जबकि आज उत्तर प्रदेश कर्फ्यू, दंगा, भय, गुंडागर्दी और अवैध कब्जे से मुक्त है। 2017 के बाद समाज और सरकार ने एक दिशा में काम किया तो इसके परिणाम सामने आए हैं।

सीएम योगी बुधवार को चरगांवा में कृषि विभाग के बीज गोदाम के समीप राजकीय महिला शरणालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 100 महिलाओं की क्षमता वाले सभी आवश्यक सुविधाओं से युक्त इस भवन के निर्माण पर 8 करोड़ 5 लाख 42 हजार रुपये की लागत आई है। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि घर छोड़ने को मजबूर किसी बेटी या घरेलू हिंसा की शिकार महिला को अब दर-दर की ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। गोरखपुर में 100 बेड का राजकीय महिला शरणालय ऐसी महिलाओं का संबल बनेगा। आधी आबादी को सम्मान और सुरक्षा देने के साथ स्वावलंबन के पथ पर आगे बढ़ाकर विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, विवाह, सुरक्षा और स्वावलंबन तक सरकार उसके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जन्म से स्नातक तक बेटी के लिए 25 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1.60 करोड़ बच्चों को यूनिफॉर्म, बैग, किताब, जूते-मोजे और स्वेटर की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 1.10 करोड़ परिवारों को सालाना 12 हजार रुपये पेंशन और प्रदेश में 65 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि अच्छे लोगों को चुनने से अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। कोरोना काल में निराश्रित हुए बच्चों को सरकार चार हजार रुपये प्रतिमाह सहायता दे रही है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई में मदद के लिए लैपटॉप भी उपलब्ध कराए गए हैं।

सीएम योगी ने रोजगार को लेकर विपक्ष, खासकर सपा पर निशाना साधते हुए कहा, 'आप गिनते जाइए, हम नौकरी बांटते जाएंगे। आप गिनते-गिनते थक जाएंगे, हम यूपी के नौजवानों को नौकरी देते-देते नहीं थकेंगे।' मुख्यमंत्री ने कहा कि मिशन रोजगार के तहत अब तक साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। अलग-अलग क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से तीन करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इनमें बड़ी संख्या में इकाइयों का संचालन महिलाएं कर रही हैं। 24 हजार से अधिक स्टार्टअप के साथ उत्तर प्रदेश का युवा अब नौकरी लेने वाला ही नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला भी बन रहा है। सीएम योगी ने कहा कि लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी के रूप में महिलाएं स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं। नारी वंदन अधिनियम के जरिए लोकसभा और विधानसभा में भी महिलाओं के प्रतिनिधित्व का रास्ता सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस बच्चों को निगल जाती थी। अकेले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करीब 500 बच्चों की मौत होती थी। सरकार के प्रयासों से आज मौत का आंकड़ा शून्य पर पहुंच गया है। उन्होंने गोरखपुर में सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में आए अभूतपूर्व बदलाव का भी उल्लेख किया। कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से वाराणसी की यात्रा अब करीब ढाई घंटे में पूरी हो रही है। सीएम योगी ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला हो या किसी कारण परिवार से बिछड़ी बेटी, बहन अथवा बुजुर्ग महिला, यह शरणालय उनका सहारा बनेगा। उन्होंने शरणालय में रह रही एक बुजुर्ग महिला का उल्लेख करते हुए कहा कि वह बोल नहीं पा रही हैं और उनके घर-पते की जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों का संबल सरकार बनती है और उन्हें उनके वैधानिक अभिभावकों से मिलाने का प्रयास करती है। मुख्यमंत्री ने महिला कल्याण विभाग से शरणालय का बेहतर संचालन करने की अपेक्षा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वामन जयंती की शुभकामनाएं देते हुए भगवान श्रीविष्णु के वामन अवतार का उल्लेख किया और उपस्थित लोगों को बधाई दी।

एक नजर

महमूद मदनी बोले- देश में मुस्लिमों को बनाया जा रहा निशाना

नई दिल्ली,एजेंसी। जमीअत उलमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने देश में मुसलमानों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पहले मॉब लिंचिंग फिर बुलडोजर और अब मस्जिदों एवं दरगाहों और मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया जा रहा है। संविधान में दिए गए अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में अराजकता जैसे हालात फैलाने की कोशिश की जा रही है। महमूद मदनी ने बुधवार को आईटीओ स्थित जमीअत मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि आज जमीअत उलमा-ए-हिंद की कार्यकारिणी की आपात बैठक में इन सबके खिलाफ जोरदार तरीके से आवाज उठाने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध करने का फैसला लिया गया है। भारत के मित्र देशों के सामने देश के मुसलमानों की ताजा स्थिति को रखने का फैसला लिया गया है। मौलाना मदनी ने कहा कि केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और प्रशासन की मिलीभगत से देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है । उनकी मस्जिदों, दरगाहों, इबादतगाह्रों को तोड़ा जा रहा है। अदालतों की विफलता की वजह से देश में इस तरह की स्थिति बनी है और इसकी वजह से देश के मुसलमानों में काफी बेचैनी भी पाई जा रही है। मौलाना मदनी ने कहा कि कार्यकारिणी की बैठक में देश के वर्तमान हालात पर विस्तार से चर्चा की गई और इस तरह के मामलों को रोकने के लिए रणनीति बनाने पर जोर किया गया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को असहाय बनाने की कोशिश की जा रही है, यह देशहित में नहीं है। इस तरह की स्थिति से उबरने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आदोलन शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि संविधान ने जो भी अधिकार दिए हैं उसका पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार, लोकतंत्र, और प्रशासन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

मणिपुर में मादक पदार्थ बरामद, उग्रवादी समेत कई गिरफ्तार

इंफाल,एजेंसी। मणिपुर में पुलिस और सुरक्षा बलों ने अलग-अलग अभियानों में एक सक्रिय उग्रवादी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान मादक पदार्थों और अवैध शराब की बड़ी खेप भी बरामद की गई। पुलिस ने बुधवार को बताया कि लिलोंग थाना की एक टीम ने नुंगई निंगथिबी बाजार इलाके से गुलाम सैयद आजाद (50) को गिरफ्तार किया। वह स्व. मोहम्मद अब्दुल समद का पुत्र है। उसके कब्जे से प्रतिबंधित 208 ट्रामाडोल कैप्सूल, 583 अल्प्राजोलम कैप्सूल और 111 डायजेपाम टैबलेट बरामद किए गए। इसी क्रम में मंगलवार को सीडीओ यूनिट काकचिंग और 43 असम राइफल्स की संयुक्त टीम ने वाईखोंग थाना क्षेत्र के लामजाओ मायाई लीकाई इलाके से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार किया। उसकी पहचान 23 वर्षीय मैबाम गुनामणि उर्फ मेरिक सिंह के रूप में हुई है। वह काकचिंग जिले के लामजाओ मायाई लीकाई निवासी मैबाम मणि सिंह का पुत्र है। एक अन्य अभियान में हीनगांग थाना पुलिस, क्यूएटी और 86वीं बटालियन सीआरपीएफ की संयुक्त टीम ने 22 सितंबर को मत्रीपुखरी में पंजीकरण संख्या एमएन03 टी-2080 वाली यात्री बस को रोका। तलाशी के दौरान बस में छिपाकर रखी गई करीब 2.1 किलोग्राम वजन की 20,000 संदिग्ध याबा टैबलेट बरामद की गईं। इस मामले में लिलोंग उसोईपोकपी निवासी 37 वर्षीय मोहम्मद अनीस खान और लिलोंग हाओरेइबी माखा लीकाई निवासी 36 वर्षीय कोरिमायुम नुरुल हक को गिरफ्तार किया गया। मामले की जांच जारी है। वहीं, इम्फाल पश्चिम जिला पुलिस ने मंगलवार को न्यू कीथेलमानबी चेकपोस्ट पर पंजीकरण संख्या एएस01 जीसी-9218 वाले टाटा ट्रक को रोका।

चुनाव आयोग कठपुतली की तरह कर रहा काम, लोकतंत्र खत्म करने के षड्यंत्र में शामिल : अखिलेश यादव

लखनऊ,एजेंसी। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि आयोग निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है और लोकतंत्र को कमजोर करने के षड्यंत्र में शामिल है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को लेकर जिस तरह के सवाल उठ रहे हैं, वे लोकतंत्र के लिए बेहद गंभीर और घातक हैं। उन्होंने कहा कि आयोग के मौजूदा नेतृत्व में हुए चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और भविष्य के चुनाव भी उसके नेतृत्व में नहीं होने चाहिए।

अखिलेश यादव बुधवार को सपा प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर खबर है कि चुनाव आयोग के दो निर्वाचन आयुक्तों ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के फैसलों पर 10 महीनों में 14 बार नोट लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के भीतर यदि उसके सदस्यों को अपने विचार स्वतंत्र रूप से रखने और अपनी आपत्तियों पर सुनवाई का भरोसा नहीं है तो यह लोकतंत्र के लिए गंभीर संकेत है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह निष्पक्ष रहकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेगा, लेकिन जिस तरह आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, उससे उसकी भूमिका पर संदेह पैदा हो रहा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता प्रभावित हुई है। उन्होंने सवाल किया कि चुनाव आयोग इस तरह के फैसले किसके इशारे पर ले रहा है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ अधिकारियों ने सपा समर्थक मतदाताओं को चिन्हित कर उनके नाम मतदाता सूची से हटाए। उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से चुनाव आयोग को बड़ी संख्या में मतदाताओं के शपथपत्र और अन्य जानकारी उपलब्ध कराई गई, लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मीरापुर, कुंदरकी, कानपुर, करहल, कटेहरी और मिल्कीपुर उपचुनावों का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि इन चुनावों में भी सपा ने धांधली और अनियमितताओं के सवाल उठाए थे, लेकिन आयोग की ओर से अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। अखिलेश ने दावा किया कि उपचुनावों में अधिकारियों की तैनाती को लेकर भी पार्टी ने सवाल उठाए थे। अखिलेश यादव ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने बिहार चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि एसआईआर के बाद वहां चुनाव जिस तरह हुआ, उससे कई सवाल खड़े हुए हैं।

त्योहारी सीजन से पहले सरकारी बफर स्टॉक से आज प्याज पहुंचेगा कोलकाता

नई दिल्ली,एजेंसी। त्योहारी सीजन से पहले पश्चिम बंगाल में प्याज की आपूर्ति बढ़ाने के प्रयासों के तहत मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) के बफर स्टॉक से प्याज लेकर कांदा एक्सप्रेस गुरुवार, 24 सितंबर को कोलकाता पहुंचेगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 1,400 मीट्रिक टन प्याज 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर उपलब्ध कराया है। त्योहारी सीजन में आम लोगों को राहत देने के लिए राज्य को और प्याज भेजा जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि सरकार पश्चिम बंगाल में प्याज की आपूर्ति बढ़ा रही है। मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) सुरक्षित भंडार से प्याज लेकर आ रही 'कांदा एक्सप्रेस' 24 सितंबर को कोलकाता पहुंचने वाली है। इसके आगमन से बड़ी मात्रा में प्याज की तेजी से आवाजाही संभव होने और खासकर त्योहारों सीजन से पहले कोलकाता और आसपास के जिलों में इसकी उपलब्धता मजबूत होने की उम्मीद है।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में एनएएफईडी और एनसीसीएफ की मोबाइल वैन के माध्यम से लगभग 1,400 मीट्रिक टन प्याज 35 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से वितरित किया जा चुका है। मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता जाने वाली कांदा एक्सप्रेस, रेल और सड़क परिवहन के हाइब्रिड नेटवर्क के माध्यम से पीएसएफ बफर स्टॉक से प्याज की सुनियोजित आपूर्ति चल रही रणनीति का हिस्सा है। एनएएफईडी और एनसीसीएफ के जरिए बफर स्टॉक से लक्षित निपटान 24 अगस्त से शुरू हुआ, और बाजार की आवश्यकताओं के आधार पर देश के विभिन्न हिस्सों में आपूर्ति धीरे-धीरे भेजी जा रही है।

कोलकाता में वर्तमान में 25 से अधिक स्थानों पर प्याज की खुदरा बिक्री की जा रही है, जिनमें मानिकतला मार्केट, कोले मार्केट, मेचुआ मंडी, रामपुरिया मार्केट और श्याम बाजार जैसे प्रमुख बाजार शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार सुफल बंगला के माध्यम से बफर स्टॉक प्याज की खुदरा बिक्री की संभावना तलाश रही है, जिससे उपभोक्ताओं को प्याज की अतिरिक्त पहुंच मिलेगी और इस पहल का दायरा भी व्यापक होगा। वहीं, बफर स्टॉक से प्याज की आपूर्ति अबतक देशभर के 100 से अधिक शहरों में की जा चुकी है। बफर स्टॉक हस्तक्षेप के बाद बाजार में उपलब्धता में सुधार का संकेत देते हुए 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में खुदरा प्याज की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं या उनमें गिरावट दर्ज की गई है। पिछले सप्ताह जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में प्याज की कीमतों में गिरावट आई है, उनमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और बिहार शामिल हैं।

जामिया के डेंटिस्ट्री फैकल्टी के छात्रों ने प्रतिष्ठित ICMR-STS 2026 रिसर्च ग्रांट हासिल किया

शबाना बेगम, वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली। जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI) की डेंटिस्ट्री फैकल्टी ने अंडरग्रेजुएट रिसर्च को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर साबित किया है। इसके दो BDS छात्रों ने प्रतिष्ठित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च-शॉर्ट टर्म स्टूडेंटशिप (ICMR-STS) 2026 रिसर्च ग्रांट हासिल किए हैं। ICMR-STS प्रोग्राम, भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ढ्ढष्टरूक्रकी एक बहुत प्रतिस्पर्धी राष्ट्रीय पहल है। इसका मकसद अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल छात्रों में वैज्ञानिक सोच और रिसर्च स्किल्स को बढ़ावा देना है। यह प्रोग्राम चुने हुए छात्रों को अनुभवी फैकल्टी मेंटर्स के मार्गदर्शन में शॉर्ट-टर्म रिसर्च प्रोजेक्ट्स करने और वैज्ञानिक कार्यप्रणाली व रिसर्च का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने का मौका देता है। ICMR-STS 2026 प्रोग्राम के तहत, हर चुने हुए प्रोजेक्ट के लिए कुल ?60,000 का स्टाइपेंड मिलता है, जिससे अंडरग्रेजुएट छात्रों को अपने स्वीकृत रिसर्च प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए आर्थिक मदद मिलती है। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि डेंटिस्ट्री फैकल्टी से चुने गए प्रोजेक्ट्स डेंटल एजुकेशन में इनोवेटिव और टेक्नोलॉजी-आधारित तरीकों पर केंद्रित हैं। ये प्रोजेक्ट्स फैकल्टी के साक्ष्य-आधारित शिक्षण, रिसर्च-बेस्ड लर्निंग और आधुनिक शैक्षिक तकनीकों को शामिल करने पर बढ़ते जोर को दर्शाते हैं।

डेंटिस्ट्री फैकल्टी से ICMR-STS 2026 अवार्ड पाने वाले छात्र हैं:

1. अनुष्का गुप्ता

प्रोजेक्ट का शीर्षक: वर्चुअल माइक्रोस्कोपी वर्सेस कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी फॉर ओरल पैथोलॉजी प्रैक्टिकल लर्निंग अमंग अंडरग्रेजुएट स्टूडेंटस: ए प्रोस्पेक्टिव क्रॉसओवर स्टडी

मेंटर: डॉ. अमन चौधरी

2. शम्स हसन खान

प्रोजेक्ट का शीर्षक: कम्पेरिज़न ऑफ़ स्टैंडर्डाइज़्ड वीडियो-बेस्ड डेमोंस्ट्रेशन (VBD) एंड NotebookLM - असिस्टेड इंस्ट्रक्शन्स विद ट्रेडिशनल इन-पर्सन डेमोंस्ट्रेशन इन ऑर्थोडॉन्टिक वायर-बेंडिंग अमंग अंडरग्रेजुएट डेंटल स्टूडेंट्स

मेंटर: डॉ. प्रियंका कपूर

दोनों प्रोजेक्ट्स अंडरग्रेजुएट डेंटल एजुकेशन में आधुनिक अवसरों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सुश्री अनुष्का गुप्ता की स्टडी ओरल पैथोलॉजी प्रैक्टिकल लर्निंग के तरीकों के रूप में वर्चुअल माइक्रोस्कोपी और पारंपरिक माइक्रोस्कोपी का तुलनात्मक मूल्यांकन करती है, जबकि श्री शम्स हसन खान की रिसर्च ऑर्थोडॉन्टिक वायर-बेंडिंग के लिए पारंपरिक इन-पर्सन डेमोंस्ट्रेशन की तुलना में स्टैंडर्डाइज़्ड वीडियो-आधारित डेमोंस्ट्रेशन और NotebookLM -असिस्टेड प्राप्त निर्देशों की प्रभावशीलता की जांच करती है। इन प्रोजेक्ट्स का चयन, फैकल्टी ऑफ़ डेंटिस्ट्री की उन कोशिशों को दिखाता है जिनका मकसद अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट्स को नए तरह के एजुकेशनल रिसर्च में शामिल होने और पढ़ाने-सीखने के नए डिजिटल तरीकों को आज़माने के लिए प्रोत्साहित करना है।जामिया मिलिया इस्लामिया की फैकल्टी ऑफ़ डेंटिस्ट्री के डीन, प्रोफ़ेसर (डॉ.) नदीम यूनुस ने इस बड़ी कामयाबी के लिए अवॉर्ड पाने वाले स्टूडेंट्स और उनके फैकल्टी मेंटर्स, दोनों को बधाई दी। उन्होंने अंडरग्रेजुएट लेवल पर रिसर्च में दिलचस्पी दिखाने के लिए स्टूडेंट्स की तारीफ़ की और रिसर्च प्रोजेक्ट्स को तैयार करने में मेंटर्स के मार्गदर्शन और हौसला-अफ़ज़ाई की भी सराहना की।यह कामयाबी एकेडमिक एक्सीलेंस, रिसर्च इनोवेशन और डेंटल एजुकेशन के आधुनिक तरीकों की दिशा में फैकल्टी ऑफ़ डेंटिस्ट्री की लगातार कोशिशों को और मज़बूत करती है। साथ ही, यह जामिया मिलिया इस्लामिया की अपने स्टूडेंट्स के बीच रिसर्च और इनोवेशन के जीवंत कल्चर को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

माओवादियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, जंगल से इंसास और राइफल सहित भारी मात्रा में गोलियां बरामद

पूर्वी सिंहभूम। जिले में भाकपा माओवादी संगठन के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। वरीय पुलिस अधीक्षक डॉ एहतेशाम वकारिब के निर्देश पर बुधवार को एमजीएम और चाकुलिया थाना क्षेत्रों के दुर्गम जंगल एवं पहाड़ी इलाकों में चलाए गए संयुक्त सघन तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने इंसास और एकेएम राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार और गोलियां बरामद की हैं। पुलिस के अनुसार, यह अभियान भाकपा माओवादी से जुड़े मंगल महतो और मालती मुर्मू की निशानदेही पर चलाया गया था।

बुधवार सुबह पांच बजे से शाम चार बजे तक चले अभियान में जमशेदपुर पुलिस, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा इकाई, कोलकाता पुलिस की विशेष कार्यबल और झारखंड जगुआर के जवान शामिल हुए। एमजीएम थाना क्षेत्र के छोटा बांकी और कुड़लुंग पहाड़ के साथ-साथ चाकुलिया थाना क्षेत्र के जोभी जंगल में सुरक्षाबलों ने संदिग्ध स्थानों की बारीकी से तलाशी ली। तलाशी के दौरान कुड़लुंग पहाड़ से एक इंसास राइफल, 85 चक्र गोलियां, तीन मैगजीन और एक सीलिंग बरामद की गई। वहीं चाकुलिया के जोभी जंगल से एक एकेएम राइफल, 147 चक्र गोलियां और दो मैगजीन बरामद हुईं।

पुलिस के मुताबिक दोनों स्थानों से कुल दो राइफल, 232 चक्र गोलियां, पांच मैगजीन और एक सीलिंग बरामद हुई है। अभियान में पटमदा के पुलिस उपाधीक्षक दयानंद कुमार, एमजीएम थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक सचिन कुमार दास, बोड़ाम थाना प्रभारी नीरज कुमार, चाकुलिया थाना प्रभारी राजेश कुमार, एमजीएम थाना के अवर निरीक्षक सुगना मुंडा और सहायक अवर निरीक्षक मजीउद्दीन के अलावा कोबरा के जवान शामिल थे। कोबरा-209 के सहायक कमांडेंट आकिफ वानी, कोबरा-203 के सहायक कमांडेंट गौरव शर्मा, झारखंड जगुआर के अवर निरीक्षक रमेश कुमार आर बरनवाल, अवर निरीक्षक संदीप बनर्जी, आक्रमण दल-27 और कोलकाता विशेष कार्यबल के निरीक्षक इश्तियाक अहमद भी अभियान का हिस्सा रहे। बरामद हथियार और गोलियों को पुलिस ने विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत जब्त कर लिया है। बरामद सामग्री और अभियान के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई और अनुसंधान किया जा रहा है।

मुद्रक, प्रकाशक, स्वामी, सैफुल्लाह सिद्दिकी द्वारा आरडी प्रिंटिंग एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-24, सेक्टर-08, नोएडा (यूपी), से छपवा कर एन-81, बटला हाउस, जामिया नगर पुलिस स्टेशन, जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित किया। सर्वाधिकार सुरक्षित, किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र दिल्ली होगा। (संपादक- सैफुल्लाह सिद्दिकी)